SHRI SUJEET KUMAR: Sir, as per the reply by the hon. Minister to my query, India is engaging with the Blue Dot Network. Sir, we have serious concerns with the BRI initiative of China, particularly with CPEC. So, my query to the hon. Minister is: Will this Blue Dot Network be seen as a counter to BRI? And, are we looking at engaging with other Indo Pacific countries to counter China on BRI?

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, during the last seven years of Prime Minister Narendra Modi ji's leadership, our foreign policy has received a greater attention and focus. Today, it is pro-active and not reactive. In fact, we do constantly and effectively engage with foreign Governments and diaspora. In the question that has been raised by the hon. Member, he wants to know whether this will be considered as a counter to the BRI. In fact, the Blue Dot Network was initiated earlier and later on it was co-opted into the Build Back Better World initiative, which has been endorsed by the G-7 and G-20 nations. Under this, India has been trying to take this ahead. On India's position on the Border Road Initiative of China, we have not been reactive on that ...(*Interruptions*)... I am coming to the answer, don't worry. Our position on BRI is very clear. I don't want to reiterate it. We have conveyed our position clearly.

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, Question Hour is over.

[*Answers to Starred and Un-starred Questions (Both in English and Hindi) are available as Part -I to this Debate, published electronically on the Rajya Sabha website under the link https://rajyasabha.nic.in/Debates/OfficialDebatesDateWise*]

---

*THE UNION BUDGET, 2022-23

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Syed Zafar Islam will continue his speech.

SHRI SYED ZAFAR ISLAM (Uttar Pradesh): Sir, thank you very much for giving me this opportunity again. Yesterday, I got the chance but I could not conclude because a lot of disruptions were there and there was time constraint. I will begin it from where I had left it yesterday. मैं याद कर रहा था कि जब बहुत ही senior opposition leader बजट

* Further discussion continued from 09.02.2022.

के बारे में अपनी स्पीच में बोल रहे थे, तो उन्होंने mention किया, 'No Data Available'. Something like that he said. I recollect, in 2013, I was visiting New York. At that time, I met with a banker. At that time, the investment manager posed me a question which I very fondly recollect now. He said, "What is this UPA Government?"

श्री उपसभापति : प्लीज़, डिस्कशन हो रहा है। Please listen to the discussion. डिस्कशन हो रहा है, कृपया हाउस में शांतिपूर्वक बैठें।

SHRI SYED ZAFAR ISLAM: Sir, there is no discipline in the opposition.

श्री उपसभापति : माननीय अब्दुल्ला जी, the discussion is going on.

SHRI SYED ZAFAR ISLAM: He asked me, "What is this UPA Government?" I said, "What happened?" He said, "It is an Under Performing Alliance." I remember that UPA stands for Under Performing Alliance. It is very clear from what they had mentioned in the manifesto of 2004 and of 2009 and in subsequent Budget presentation and schemes. I want to remind them that they mentioned about providing electricity to everyone. Did they? It is us. It is under the leadership of the hon. Prime Minister that we are providing electricity to every single household. सर, उन्होंने वायदा किया था कि हम जल्दी घरों तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा था कि हम terrorism खत्म करेंगे, लेकिन terrorism को हम खत्म कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे वायदे किए थे जैसे कि हम economy के लिए weaker section को रिज़र्वेशन देंगे। सर, वह काम भी हमने किया। उन्होंने जितने भी काम बोले थे, उनको पूरा करने का काम हमने किया है। ऐसा इसलिए है कि वह Under Performing Alliance थी। सर, वह यूपीए सरकार, वह Under Performing Alliance इसी तरह से जानी जाती थी। इसलिए उन्होंने ही जो दुनिया की five fragile economies थीं, वह चरमराती इकोनॉमी 2014 में हमारे खाते में छोड़ी।

सर, मैं सुन रहा था कि उन्होंने जॉब के बारे में कहा। अभी बड़े विस्तार से हमारे सीनियर मिनिस्टर ने उसके बारे में जवाब दिया। उनको जो response मिला, तो शायद उनका झोला भर गया होगा, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने CMIE की methodology के बारे में जो कहा, उससे शायद मैं personally इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन फिर भी उन्होंने जो CMIE डेटा का reference दिया, तो मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि जो उन्होंने कहा वह बहुत मिसलीडिंग था, क्योंकि CMIE डेटा monthly basis पर पब्लिश होता है और उन्होंने एक वीक का एक नम्बर उठाकर पूरे सदन को मिसलीड करने की कोशिश की है। अगर आप उस वक्त जाकर देखें और आज मैं चैलेंज करता हूं कि सदन में आकर वे बताएं कि जो नम्बर उन्होंने कहा था, वह जनवरी के डेटा का नम्बर था। सर, वह जनवरी के एक वीक के डेटा का नम्बर था, पूरे जनवरी महीने का डेटा नहीं था। अगर आप जनवरी का डेटा उठाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि pre-pandemic level 7.2 जो unemployment rate as per the CMIE report, वह आज घटकर 6.6 हो गया है। सर, उससे ज्यादा important है कि

यह एक सर्वे होता है, informal और formal, सभी सेक्टर्स का होता है, लेकिन ईपीएफओ को जो डेटा है, वह बिल्कुल constant है because there is a payroll method. There is a record which is available because यह formal सेक्टर में है। आप उसके डेटा में देखें कि पिछले साल वह 0.5 मिलियन से बढ़कर आज 1.22 मिलियन तक हो गया है, यानी एक मिलियन से ज्यादा जॉब्स हम बार-बार क्रिएट कर रहे हैं और month after month create कर रहे हैं। What does that suggest कि जॉब्स तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन आप मिसलीड कर रहे हैं। यह फॉर्मल सेक्टर में है, यह white collar job है। ईपीएफओ की जॉब white collar job होती है। सर, जो blue collar jobs हैं - अगर आप thumb rule देखें तो पाएंगे कि अगर white collar job एक है, तो मिनिमम 5 blue collar jobs होंगी। अगर हम हर महीने दस लाख जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि informal sector और formal sector में भी जो blue collar jobs हैं, वे कम से कम 60-70 लाख अपने आप ही होंगी। सर, जो ये नौकरियां हैं, उनको भी further analyze कीजिए।... (**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि यदि आपको आपस में बात करनी है, तो जैसा माननीय चेयरमैन साहब कहते हैं कि कृपया आप बाहर जाकर गैलरी में बात कर लें। जो माननीय सदस्य अपनी बात बोल रहे हैं, वे सभी आपकी attention चाहते हैं। इसलिए कृपया यहां पर आपस में बातचीत न करें। जफ़र इस्लाम जी, आप अपनी स्पीच जारी रखें।

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, मैं बता रहा था कि जो EPFO का data है, अगर उसको further analyze करेंगे, तो आपको लगेगा कि youth को यह हमारा demographic dividend है। सर, हमारी सरकार की इस तरह की constructive policy है, हमारा Budget इस तरह से पेश होता है, इसीलिए हम 'अमृत काल' कहते हैं, लेकिन 'अमृत काल' का मतलब है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसा सुनहरा देश हो, जिसमें सबके लिए नौकरियां हों, सबके लिए सारी सुविधाएं हों, इसलिए हम सभी दिशाओं में काम कर रहे हैं।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) *पीठासीन हुए*]

सर, अभी हमने देखा और बड़े लोगों को यहां पर सुना, उन्होंने हमें बजट पर ज्ञान दिया और कई तरह की टिप्पणियां कीं। हमने उनको सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि हवा में ऊपर उड़ान लेनी चाहिए, सर, हम तो ज़मीन पर हैं। ज़मीन पर रहकर हम ज़मीन की situation देखते हैं, इसीलिए आदरणीय प्रधान मंत्री जी सबसे ज्यादा popular and admired leader हैं, क्योंकि वे ज़मीन पर ही लोगों के साथ मिल-जुल कर, रूबरू होकर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं।

सर, कल माननीय सदस्य subsidy की बात कर रहे थे। वे कह रहे थे कि subsidy कम हो गई। सर, मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि आप subsidy की क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको subsidy के बारे में बताना चाहता हूं कि Financial Year 2022, में हमने क्या subsidy दी थी - उसमें हमने 3.36 की subsidy propose की थी। सर, हमारी सरकार

compassionate सरकार है, हमारी Government, compassionate Government है, हमारी दोनों सरकारों ने principle of 'C' follow किया है, आपके लिए principle of 'C' corruption था, वह हमारे लिए compassionate है। हम compassionate Budget पेश करते हैं, हम देखते हैं कि जब भी समाज में किसी वर्ग को जरूरत होती है, तो हमारा subsidy level या सरकारी खजाना खुल जाता है। आपने देखा होगा कि हमने 2021 में क्या किया। जब हमने देखा कि लोगों को जरूरत है, तो हमने बड़ा contribution किया, उसके लिए allocation किया, 'आत्म-निर्भर पैकेज' के द्वारा हमने marginalized sections of society को बढ़ाया, लेकिन अब जब हालात बेहतर हो रहे हैं, आपको दिख रहा है कि नौकरियां वापस आ रही हैं, "मनरेगा" में demand कम हो रही है, तो जाहिर है - हमारी यह compassionate सरकार है, यह conservative Budget reference point की तरह देती है, लेकिन अगर कल को जरूरत पड़ती है, तो हमारी सरकार लोगों के लिए सरकारी खजाना खोल देती है ताकि किसी को भी कोई असुविधा न हो।

सर, हम पूछना चाहते हैं कि जो लोग इसको criticize कर रहे हैं, वे Budget numbers को, Fiscal Deficit के numbers को, Fiscal Deficit is 6.9 per cent. सर, आपको समझना चाहिए कि जो सारे लोग हैं, वे इस बात के लिए बधाई दे रहे हैं कि हमने बहुत ही conservative number दिया है, even though जो हमारे Revenue Estimates हैं, वे बहुत ही conservative हैं, इसलिए कि हमें मालूम है कि जिस तरह की growth देखी, हम F.Y. 2021-22 Budget Estimates को देखें, तो हमने जो tax collection का 9.9 per cent दिया था, वह 10.8 per cent हुआ और उसकी 25 per cent growth हुई है, लेकिन इस बार के F.Y. 2022-23 में देखें, तो फिर हमने बहुत ही conservative Budget रखा है 9.9 per cent का। इससे क्या समझ में आता है, सर, कि हम बहुत ही conservative Revenue Estimates दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। वे बात करते हैं कि जो आपने assumption लिया है,जो numbers दिए हैं fertilizers के लिए, उसमें subsidy कम होगी। भाई, आप थोड़ा और ज्ञान ले लेते, थोड़ा और analyze कर लेते। आपने तो Budget पहले भी present किया है। Absolute amount में, सर, मैं कह रहा हूं कि जितनी भी हमने subsidy allocate की है, उसमें आठ पैसे पिछले F.Y. 2021-22 Budget में और F.Y. 2022-23 Budget में एक रुपये में आठ पैसे subsidy में जाते हैं, जो पिछली बार भी जा रहे थे, इस बार भी जा रहे हैं। हो सकता है कि आप percentage to GDP देख रहे हों। मैं समझता हूं कि percentage to GDP को देखने का एक अलग नज़रिया है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखें ....(**समय की घंटी**).... सर, मुझे आज 15 मिनट बोलने के लिए समय मिला है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No, no. ...*(Interruptions)*...

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, हमारे लीडर ने कहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your Party has ten more speakers. ...*(Interruptions)*... Where is the time? ...*(Interruptions)*...

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, मुझे बोलने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your Party has ten more speakers. ...*(Interruptions)*... Please conclude now.

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, ऐसी बातचीत में मेरा कल भी flow रह गया था। सर, मुझे complete कर लेने दीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now.

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, अब मैं brief में बोलता हूं। सर, आप welfare sector में सारे welfare के numbers देख लीजिए ex-subsidy, तो आपको दिखेगा कि हमने welfare में भी इस बार ज्यादा budgetary allocation किया है। यह compassionate सरकार है, यह सरकार corruption वाली सरकार नहीं है। हम भी principle of 'C' follow करते हैं, लेकिन यह सरकार compassionate है, इसलिए जब भी जरूरत पड़ती है, हम अपना खजाना खोल देते हैं। सर, अब मैं थोड़ी टिप्पणियां करूंगा कि लोग कह रहे हैं कि इस बजट में क्या है।

महोदय, बजट में तीन बड़ी चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो आत्मनिर्भर बनने की बात है। इसमें पूरी तरह से पेशकश की गई है कि देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसलिए पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं, पॉलिसी सपोर्ट की है, फिर वह चाहे पीएलआई स्कीम का दें, चाहे half-a-trillion dollar का मैन्युफैक्चरिंग में, स्पेस में हो, आप देख रहे हैं कि पीएमआई नंबर कैसा है। यह जो 5.6 नंबर है.. (**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, you conclude. I will call the next speaker. ...*(Interruptions)*... Please.

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, मुझे थोड़ा कम्प्लीट करने दीजिए। .. (**व्यवधान**)..बात तो कहने दीजिए। .. (**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No; there are other speakers from your party. ...*(Interruptions)*... They will not have time. ...*(Interruptions)*... Why don't you understand? ...*(Interruptions)*... You spoke yesterday and we have given you time even today.

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, मैं अपने तीन प्वाइंट्स कम्प्लीट कर लूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इस पूरे बजट में तीन बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं सिर्फ तीन चीज़ों के बारे में बोल रहा हूं।

महोदय, पहली चीज़ यह है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वह 2.9 per cent of GDP, जो पिछली बार 2.6 था, यह हिस्टोरिकल है। इतना ज्यादा बजटरी एलोकेशन है, कैपिटल का

एक्सपेंडिचर नहीं है। Virtuous cycle बनाने के लिए कैपेक्स जरूरी है, अतः प्राइवेट कैपेक्स भी शुरू होगा और नौकरियाँ भी बढ़ेंगी।

महोदय, दूसरी चीज़ यह है कि fiscal consolidation का जो विषय है, उसका रोड मैप बिलकुल साफ है, कंज़र्वेटिव है। यह बिलकुल साफ है और लोग इसको एप्रिशिएट कर रहे हैं।

महोदय, जो तीसरी चीज़ है, वह यह है कि टैक्स को लेकर जो एक एनवायरन्मेंट था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, यह टैक्स, वह टैक्स, वह बिलकुल स्टेबल है और पूरी क्लैरिटी के साथ दिया गया है। इसके नंबर बिलकुल साफ-सुथरे हैं, बजट में क्लैरिटी है, लेकिन.. (**व्यवधान**)..मैं बस एक शेर पढ़कर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। .. (**व्यवधान**)..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. ...*(Interruptions)*... नहीं। Please. Please. ...*(Interruptions)*... I will call the next speaker. ...*(Interruptions)*...

श्री सैयद जफर इस्लाम : सर, बस एक शेर पढ़ने दीजिए। .. (**व्यवधान**)..मुझे एक छोटा-सा शेर कहना है। .. (**व्यवधान**)..

न जाने कौन सी शिकायत का हम शिकार हो गए ,
जितना दिल साफ़ रखा, उतना गुनहगार हो गए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please. Please. No. ...*(Interruptions)*... I am calling the next speaker. ...*(Interruptions)*... Now, Shrimati Chhaya Verma.

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : श्रीमती छाया वर्मा, आप बजट पर बोलिए।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़) : उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अपनी पार्टी के लीडर को भी धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब देते हुए उधर से एक व्यक्ति, हमारे एक माननीय सांसद जवाब दे रहे थे और वे ऐसे बोल रहे थे कि जैसे वे पंजाब के प्रत्याशी हैं और हम सभी पंजाब के मतदाता हैं - वे ऐसी स्पीच दे रहे थे। वे बोलते-बोलते यह भी बोल गए कि सही मायने में 2014 में देश आज़ाद हुआ। मैं यह कहना चाहती हूं कि ऐसा बोलकर आप उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिन्होंने देश के लिए अपनी कुरबानी दी, उनका अपमान कर रहे हैं। गुलामी की दासतां आप क्या जानें रमेश बाबू, गुलाम देश को आज़ादी दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों को कितनी यातनाएं झेलनी पड़ीं, कितने अन्याय सहने पड़े, कितने अत्याचार सहने पड़े, यह आप उनके परिवार से जाकर पूछिए कि उन्होंने कैसी यातनाएं झेली हैं। आप तो उन नाखून कटाने वालों में भी नहीं हैं, इसलिए आप इसको क्या जानेंगे।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा सौभाग्य है कि महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बारे में जब प्रधान मंत्री जी अपना उद्बोधन दे रहे थे, तो मुझे वह सुनने का मौका मिला। मैं सदन में नहीं, बल्कि बाहर बैठकर उनको सुन रही थी। वे कह रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ, तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मजदूर लोगों को मुंबई से ट्रेन में और बस में बिठाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया, इसलिए कोरोना हुआ। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आप बताइए कि लॉकडाउन के समय कौन-सी ट्रेन चल रही थी और कौन-सी बस चल रही थी? महामहिम के अभिभाषण पर प्रधान मंत्री जी के वक्तव्य में इतनी असत्य बात प्रधान मंत्री जी के मुँह से शोभा नहीं देती। .. (**व्यवधान**)..इतनी गलत बात बोलना उचित नहीं है। .. .(**व्यवधान**)... कोरोना कैसे बढ़ा, यह आप सभी जानते हैं। ...(**व्यवधान**)... आप मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगे थे। ... (**व्यवधान**)... जब आप 'नमस्ते ट्रम्प' कर रहे थे ... (**व्यवधान**)... तब देश में कोरोना आया, कोरोना कांग्रेस पार्टी के कारण नहीं आया। ... (**व्यवधान**)... हमारे प्रधान मंत्री जी अपनी पूरी स्पीच में बोल रहे थे कि कांग्रेस नहीं होती, तो यह नहीं होता, कांग्रेस नहीं होती, तो वह नहीं होता, क्या आप भूल गए कि 2002 में क्या हुआ था? . . . (**व्यवधान**)...

श्री सुशील कुमार मोदी (बिहार) : यहां बजट पर चर्चा हो रही है। .. (**व्यवधान**)..

श्रीमती छाया वर्मा : हाँ, हाँ, मैं बजट पर आऊंगी। .. (**व्यवधान**)..

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : श्रीमती छाया वर्मा, आप सब्जेक्ट पर आइए। . . . (**व्यवधान**)..

श्रीमती छाया वर्मा : उस समय, वहाँ पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री थे। उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आएगी, जब मैं विदेश में जाऊंगा कि मेरे देश में, मेरे राज्य में ऐसा हुआ है। .. (**व्यवधान**)..उन्होंने ऐसा कहा था। .. (**व्यवधान**)..मैं यह कहना चाहती हूं कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी से कुछ सीखिए। उपसभाध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट पर आती हूं। .. (**व्यवधान**)..माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, बजट पर जाने से पहले हमें समझना होगा कि यह बजट आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए है, सरकार के लिए है या सरकार के मित्रों के लिए है। 2022-23 के बजट में 'गरीबन का का बा', 'हीरे की कीमत कम करबा और 'artificial jewellery की कीमत बढ़एबा'। आपने हीरे की कीमत तो कम कर दी है, जिसको कौन पहनता है? इसको बड़े आदमी पहनते हैं, पैसे वाले लोग पहनते हैं। शक्ति भाई, आप बताएँगे कि हीरे का व्यापार कहाँ होता है? यह सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सूरत और गुजरात से कौन आता है, अमी बहन, आप बता दीजिए। आपने बजट में हीरे की कीमत कम कर दी। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि "जेखर गोड़ में काँटा गड़थे तेने पीड़ा होथे", मतलब जिसके पैर में काँटा चुभता है, उसी को दर्द महसूस होता है।

महोदय, मैं महिला हूँ, हमारी वित्त मंत्री जी भी महिला हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि आप 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा देते हैं, लेकिन उस नारे में सार्थकता कितनी है? उसमें एक अंश मात्र सार्थकता नहीं है। हम पेपर उठा कर देखें। आप हर दिन पेपर देख लीजिए, टेलीविजन

देख लीजिए, एक ही चीज के अनेक समाचार पढ़ने को मिलते हैं कि इस महिला के साथ बलात्कार हुआ, इसके साथ रेप हुआ, इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। पेपर के हर पन्ने में हमें यही सब देखने और सुनने को मिलता है। अगर सही मायने में आप अपने नारे को सार्थक करना चाहते हैं, तो मैं कहती हूँ कि आपकी सरकार के पास बहुमत है, जैसे आपने रात को 8 बजे नोटबंदी कर दी, GST ला दिया, आपका बहुमत है, आप सदन में कोई भी बिल पास कर लेते हैं, तो मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि आपका बहुमत है, आप विधान सभा और लोक सभा में महिला आरक्षण बिल लाइए। हमारी सोनिया गाँधी जी कहती हैं कि हम इसका समर्थन करेंगे। आप उस बिल को लाइए, हमारी पार्टी समर्थन करेगी और तब सही मायने में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का नारा सार्थक होगा, वरना यह केवल नारा ही रह जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। हमारी नेता, प्रियंका गाँधी जी ने न केवल यह बात कही कि हम 40 प्रतिशत महिलाओं को टिकट देंगे, बल्कि टिकट भी दिया है। वे "लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ" की तर्ज पर चुनाव लड़ रही हैं। **...(व्यवधान)...** उनके पिताजी, देश के पूर्व प्रधान मंत्री, भारत रत्न, राजीव जी ने पंचायत और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण देकर महिला आरक्षण को लागू किया और मैं उसी के बलबूते, कहीं न कहीं उसी के आशीर्वाद से यहाँ पर खड़ी होकर बोल रही हूँ। मेरी जैसी अनेक महिलाएँ पंचायती राज और नगरीय निकायों से होती हुई यहाँ तक पहुँची हैं। आपके पास बहुमत है, आप नारे तो बहुत देते हैं, लेकिन उस नारे को सार्थक भी करिए, तभी सही मायने में वह नारा नारा रहेगा, वरना वह केवल एक कागज के पन्ने में लिखा हुआ शब्द हो जाएगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट में ड्रोन खेती के बारे में बात आई है। अब ड्रोन खेती कौन करेगा? बड़े किसान करेंगे, छोटे किसान तो कर नहीं सकते। खेती सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उपक्रम है। आप जितना अधिक आधुनिक चीजों को खेती में लाएँगे, उतने अधिक लोग बेरोजगार होते जाएँगे। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आप आधुनिक खेती करिए, लेकिन उसमें रोजगार की दर घटती है। आपने स्वामीनाथन कमिटी की सिफारिशें तो लागू की नहीं। कृषि में आमदनी दोगुनी होगी, ऐसा कह कर आपने पिछले समय बजट में लोगों को भ्रमित किया। कृषि में आमदनी तो दोगुनी हुई नहीं, लेकिन लागत जरूर दोगुनी हो गई। आपके पेट्रोल और डीजल के मूल्य बढ़ गए, आपके कृषि उपकरण के मूल्य बढ़ गए, आपने ट्रैक्टर पर GST double कर दिया। इस प्रकार से जितनी लागत है, वह double हो गई, लेकिन कृषि में आमदनी तो कुछ भी नहीं बढ़ी। आज लोग कृषि से पलायन कर रहे हैं। आज लोग खेती नहीं करना चाह रहे हैं। आपने यूरिया का दाम बढ़ा दिया। लोग खेती से मुँह मोड़ रहे हैं। अगर सही मायने में खेती के बारे में जानना है और सही मायने में आपको खेती की आमदनी दोगुनी कैसे हो रही है, यह जानना है, तो आप छत्तीसगढ़ आइए। आप छत्तीसगढ़ की सरकार से कुछ सीखिए। हमारे यहाँ तीन साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के पूरे किसान कर्जमुक्त हो गए हैं। वहाँ एक क्विंटल धान का समर्थन मूल्य 2,500 रुपए मिलता है। हमारी सरकार हर किसान को, साल में एक बार, एक एकड़ पर 9,000 रुपये देती है, जो भारत के किसी भी राज्य में नहीं होता है। साथ ही हर साल 7,000 रुपये उन किसानों को भी दिए जाते हैं, जिनके पास एक एकड़ जमीन या थोड़ी सी भी ज़मीन नहीं है। ऐसा भारत के किसी भी राज्य में नहीं होता है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी - ये चार प्रोजेक्ट्स लाकर हमारी सरकार किसानों की आमदनी को दोगुना कर रही है। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन आप वहां स्वयं आकर देखिए कि किस ढंग से खेती

की आमदनी को दोगुना किया जाता है। वहां के नौजवान अब खेती की ओर बढ़ रहे हैं और खेती करने की सोच रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनके कारण केन्द्र सरकार ने हमारे यहां के यशस्वी मुख्य मंत्री, श्री भूपेश बघेल जी को कई बार यहां बुला कर पुरस्कार दिया है। यदि आपको खेती के बारे में कुछ सीखना है, तो आप छत्तीसगढ़ में आइए, वहां की योजनाओं के बारे में जानिए, सीखिए।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, 'मनरेगा' एक कल्याणकारी योजना है। जिस समय लॉकडाउन लगा, उस समय सारे मज़दूर पलायन करके अपने-अपने गांव की ओर चले गए। ऐसे में उनके पास 'मनरेगा' ही एक ऐसा काम था, जिससे उन लोगों को रोज़गार मिला, खाना-पीना मिला और उनका कुपोषण घटा। लेकिन अभी के बजट में आपने क्या किया है? आपने 'मनरेगा' के बजट को कम कर दिया है। जब आपने 'मनरेगा' का बजट ही कम कर दिया है, तो लोगों को काम कहां से मिलेगा, लोगों का पेट कैसे भरेगा और उनका कुपोषण कैसे दूर होगा? मैं सदन से मांग करती हूं कि 'मनरेगा' को 100 दिन के बदले 365 दिन करें। इसके साथ बहुत से राज्यों को अभी तक 'मनरेगा' का पैसा भी नहीं मिला है, including छत्तीसगढ़, तो उस पैसे को आप दें, तभी सही मायने में लोगों को रोज़गार मिलेगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट में क्रिप्टो करेंसी की बात की गई है। क्रिप्टो करेंसी को अभी तक मान्यता तो मिली नहीं है, लेकिन उसको आपने बजट में ला दिया, इसका मतलब यह है कि आपने क्रिप्टो करेंसी को मान लिया है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कौन करता है? इसका उपयोग तो पैसे वाले लोग ही करेंगे, गरीब आदमी या साधारण आदमी को इस क्रिप्टो करेंसी से कोई लेना-देना नहीं है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या में, भारत के कैदियों की संख्या सबसे ज्यादा - 76 प्रतिशत है। आपके पास वकील नहीं हैं, आपके पास जज नहीं हैं, आपके पास न्यायालय में काम करने वाले बाबुओं की पूरी संख्या भी नहीं है, इसीलिए आज 76 प्रतिशत कैदी जेल में हैं और अपने न्याय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।

महोदय, मुझे यह बताते हुए और भी अधिक चिंता हो रही है कि आपकी सरकार के राज्य में स्वयं जज न्याय मांगते फिर रहे हैं, क्योंकि जजों को ही न्याय नहीं मिल रहा है, यह परिस्थिति आज उत्पन्न हो गई है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है - 'अमर जवान ज्योति', जिसको आपकी सरकार ने बुझा कर दूसरी जगह स्थापित कर दिया है। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने, जितने भी छत्तीसगढ़ के जवान शहीद हुए हैं, उनके लिए अलग से 'अमर जवान ज्योति' स्थापित की है। यहां इन्दिरा जी ने जिस 'अमर जवान ज्योति' को जलाया था, उसको आपने हटा दिया, लेकिन हमारे राहुल जी छत्तीसगढ़ में जाकर, वहां 'अमर जवान ज्योति' का भूमि-पूजन करके आए हैं, जो छत्तीसगढ़ में अनवरत जलती रहेगी। यह बहुत ही संवेदनशील और भावनात्मक इश्यू है कि आपने यहां से 'अमर जवान ज्योति' को हटाने का काम किया। नागपुर में वर्धा ग्राम बना हुआ है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में 35 एकड़ जमीन पर, राजधानी रायपुर में नया वर्धा ग्राम बनने जा रहा है और उसका शिलान्यास भी हमारे राहुल जी ने किया है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, ये लोग गांधी को नहीं, गोडसे को मानने वाले लोग हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में कालीचरण नाम का एक व्यक्ति गया हुआ था, जिसने वहां जाकर धर्म

संसद की। उस धर्म संसद की आड़ में वह गांधी जी को वहां गाली देने लग गया और 'गोडसे जिन्दाबाद', 'गोडसे को नमस्कार', ऐसा कहने लग गया। इनकी पार्टी के लोगों ने भी उसका समर्थन किया, उसका बचाव किया। लेकिन हमारी सरकार ने उस कालीचरण नाम के व्यक्ति को जेल में डाल दिया है, वह व्यक्ति अभी जेल में है। इसी से यह बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि कौन गांधी जी के साथ है और कौन गोडसे के साथ है, यह बात आपको समझनी चाहिए।

महोदय, यह बजट पीपीपी मॉडल पर आधारित है। अपने दोस्तों के सुझावों से, किसके लिए कितना बजट रखा गया है, यह इसमें तय करते हैं। अभी पांच राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए कुछ महीनों से पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पांच राज्यों के चुनाव खत्म हो जाएंगे, मतदान हो जाएगा, उसके बाद जनता पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस को महंगे दामों पर खरीदने के लिए तैयार रहे।

महोदय, यह सरकार 56 हज़ार करोड़ रुपये का सेन्ट्रल विस्टा बना रही है, अभी कोरोना काल में इसकी क्या आवश्यकता थी? पिछले दो सालों से हम सभी सांसदों का 'एमपीलैड' का पैसा आपने ले लिया, आपने किसी से कुछ नहीं पूछा और न किसी से सलाह ली, जबकि आपके सांसद ज्यादा हैं, लेकिन आपके सांसद बोल नहीं सकते, वे चुप रहते हैं। 'मन की बात' रेडियो पर हम सब सुनते हैं, लेकिन जन की बात कौन सुनेगा, जन की बात आप सुनते ही नहीं हैं, लोगों की समस्याएं आप सुनते ही नहीं हैं।

महोदय, इस देश में तरक्की केवल दो लोगों की ही हुई है - एक सबसे अमीर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के मित्र, जो विश्व में सर्वाधिक पैसे वाले व्यक्ति हैं। तीसरे किसी व्यक्ति की तरक्की नहीं हुई है। आपने जितना ढोल पीटना है, पीट लीजिए, जितने नारे देने हैं, दे लीजिए, जितना बोलना है, बोल लीजिए, लेकिन अभी जिन पांच राज्यों में चुनाव हैं, वहां का रिजल्ट आपको बतायेगा। सत्ता का अहंकार जब सिर चढ़कर बोलता है, इसका परिणाम आपको पांचों राज्यों के चुनाव में दिखेगा और वहीं से आपका पतन शुरू हो जाएगा।

महोदय, इमारत जितनी ऊंची होती है, खतरा उतना ही अधिक रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, at the outset, I would like to convey the message of....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Shri Sujeet kumar, your party has eight minutes' time and there are two speakers. So, please be brief.

SHRI PRASANNA ACHARYA (Odisha): Sir, we have requested the Minister of Parlimentary Affairs and he has given us some extra time; that is separate.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Eight minutes' time is left for your party and another speaker is there, so, please be brief.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, that is taken care of.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please keep that in mind, I am just telling you.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, at the outset, I would like to convey the message of my hon. Chief Minister who has appreciated the growth focus of the Budget. I quote him, "the focus of the Budget on technology and infra-led growth will have a positive impact. The proposed tech-led development in health and education will help the country to a large extent in this pandemic situation. The PLIs in fourteen sectors and extension of Emergency Credit Linked Guarantee Scheme would be helpful in mitigating supply-side constraints". Sir, definitely, increased capital expenditure by 24.5 per cent, setting up of multi-modal logistics park, focus on leveraging technology to make India a leader in the digital space, reduction of tax for cooperatives are all highly laudable initiatives taken by the hon. Minister and are praiseworthy. Sir, I must also take this opportunity to salute the entrepreneurial spirit of our youth and the way they are positioning India in the start-up ecosystem needs to be applauded. Sir, I also commend the hon. Minister for the steps taken by the Government to boost green energy and also coming out with policies such as battery swapping policy for EVs and Sovereign Green Bonds which will help mobilise resources for green infrastructure. However, my Chief Minister has also flagged several concerns particularly, the reduced allocation for various social sectors such as agriculture, rural development, health, women and child development. I would like to share some of those concerns with the House and hope that the Government will take serious note of it. But, before that I would also like to highlight two or three other points very quickly. One is my personal concern regarding the abysmal spending on R & D in this country. Sir, you would be shocked to know that we, as a nation, spend only 0.7 per cent of our GDP on R & D.

12.00 **Noon**

When compared this with other nations, Sir, China spends 2.2 per cent, Israel 4.9 per cent, South Korea 4.6 per cent, US 3.6 per cent of the GDP on R&D. Sir, we all know that during this pandemic how our scientists and doctors have made us proud by coming up with vaccines in such a duration amongst such constraints as reduced resources. But still, Sir, we have hiked the health R&D only by 3.92 per cent in the Budget. What is 3.92 per cent? Sir, Defence R&D has been hiked by 9.5 per cent and 25 per cent of this has been earmarked for strat-ups. Definitely it is praiseworthy

and this will hopefully incentivize the private sector to enter the Defence R&D. But, Sir, R&D Budget has been reduced for Atomic Energy, for Biotechnology, for Science and Technology. So, for this Government, I perceive that R&D is not a priority. Sir, now I come to Defence very quickly. Sir, way back in 2017-18, the Parliamentary Standing Committee on Defence had recommended spending 3 per cent of our GDP on Defence. We have not reached this number yet. Currently, we are spending roughly 2 per cent of our GDP on Defence and we have two hostile neighbours on both of our borders. So, I hope the Government is cognizant of this. Defence accounted for 16.8 per cent of India's Budget Estimates pre-pandemic, which has come down to 13.31 per cent now. Sir, another disappointing miss in this Budget is the dedicated non-lapsable fund for modernisation of the Defence Forces as recommended by the 15th Finance Commission. There is no indication in this Budget of this critical reform. Sir, I am very much aware that enhanced allocation to Defence will leave less pie for social sectors. This always is a tricky balance between the guns and the butter, missiles and Mid-day Meals. But, Sir, I hope that the Government makes this tricky balance properly. As a party, Biju Janata Dal and our Party President, hon. Naveen Patnaik have always stood with successive Governments when it comes to matters of national security. Sir, with regard to fiscal federalism, I would like to draw the attention of the Government, particularly this Government, to two issues. One is the reduced divisible pool of taxes for the States and the continuing expansion of the Centrally-sponsored schemes. Sir, the House will be shocked to know that the indivisible pool of taxes has increased from 7.5 per cent to roughly 20 per cent in 2021-22 BE. Sir, these taxes, cess and surcharges, are not shared with the State Governments. Is this cooperative federalism? Sir, the Finance Commission had recommended 41 per cent of the tax pool to be shared with the States. But because of this enhanced cess and surcharges by the Central Government, only 30 per cent is now left with the States. Sir, the continuing expansion of the Centrally-sponsored schemes, even while shifting the fiscal burden on the States is having a huge negative impact on States like Odisha and other poor States and also impinging on the fiscal liberty of the States. ...*(Interruptions)*.. Sir, I come to the inadequate social sector spending now. There is no mention of price rise or inflation in the Budget. There is no mention of unemployment in the Budget. The MGNREGA budget has been reduced by 25 per cent. Sir, only yesterday I came from my District of Kalahandi in Odisha and I can tell you how the poor labourers and people who are dependent on MGNREGA, because it is a demand-driven scheme, are affected because of this. It is also pertinent to note that Rs.700 odd crores, which is pending for material component, has not been paid to the Government of Odisha

by the Government of India. Sir, I am reminded of the French Nobel Laureate, Andre Gide who said 'that everything that needs to be said has already been said, but since no one was listening, everything must be said again.' Sir, the Kothari Commission way back in 1964, had recommended 6 per cent of the GDP for education.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): You have another Member to speak. ...*(Interruptions)*.. You are exhausting all the time of the party. ...*(Interruptions)*.. Please conclude. ...*(Interruptions)*.. Please conclude now.

SHRI SUJEET KUMAR: Please allow me to speak. ...*(Interruptions)*.. I am concluding. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I can allow but your other Member will not get time. ...*(Interruptions)*..

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, 6 per cent of India's GDP should be spent on education. Sir, we have a New Education Policy. We are talking lofty things about education, but we are spending only 3 per cent of India's GDP on education despite all these lofty goals. Sir, another worrying aspect is that the Union health expenditure is down by 0.41 of the GDD in 2021-22. In this COVID pandemic year, they are reducing the allocation to health. Sir, I can go on and on, but because of paucity of time, I will come back to my home State of Odisha. My Chief Minister has raised, time and again, issues of negligence in the areas of tele-density, railway network, banking, coal royalty, industrial corridor, drinking water and cutting of funds for Scheduled areas like the KBK region.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, Odisha has received global acclaim for its disaster management. Yet, the Disaster Response Fund, which should have been on par with the Himalayan States, has not been mandated 90:10 for Odisha. Sir, I will give an example. In the last three years, we received four cyclones--Titli, Fani, Amphan and Yaas. Yet, the Government of India is unwilling to change the sharing pattern of Disaster Response Fund to 90:10.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your time is over and please conclude now. Or else, I will call the next speaker.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, I will conclude now. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Hon. Members, don't make running commentaries. Please listen to him.

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, the railway density in Odisha is only 17 as opposed to the national average of 21. We are thankful to the Minister of Railways for sanctioning Rs.9,700 crore this year. But, I hope, the Ministry of Railways will not lower this in the Revised Estimates. Sir, connectivity is the lifeline of any nation. I strongly urge the Government to take care of the need of Odisha in terms of railway density, highways and banking.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your mike is off now. It will not go on record now. Prof. Manoj Kumar Jha, please.

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार) : धन्यवाद, ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर। मैं आज शुरुआत आप ही से करता हूँ। चूँकि मेरे हिस्से में वक्त थोड़ा कम है, इसलिए मैं कहता हूँ :

"मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे,
बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरज़ू रहे।"

वाइस चेयरमैन सर, मैं आपसे वह sense of protection भी चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से यह कहूँ कि इस देश में कैबिनेट में जितने विभाग हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग Finance Ministry है और उस मिनिस्ट्री में जो भी लोग हैं, मुझे उनकी चिंता होती है, क्योंकि मुझे पता है कि pandemic के साये में नीति और नीयत तय करना आसान नहीं होता, आपके लिए तो और भी आसान नहीं होता। जब मैंने Cabinet reshuffle देखा, जब क्रेडिट की बात होती है, तो क्रेडिट तो तय है कि यह कहाँ जाएगा, हाँ, अगर बदनामी आनी है, तो किसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा, यह भी पता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, इस बजट को अमृत काल का बजट कहा गया। अब जब मैं बीते कुछ वर्षों की कार्यशैली देखता हूँ, तो मुझे स्पष्ट दिखता है कि अमृत किनके लिए है और विष किनके लिए है। सर, अमृत मित्रों के लिए है और यह पर्याप्त मात्रा में है। वे इतना अमृत पी लेंगे कि उनका पेट और फूल जाएगा, लेकिन एक महती जनता, एक विशाल जनता के हिस्से में विष के अलावा कुछ नहीं आ रहा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं डिफेंस के लिए हुए ऐलोकेशन से अपनी बात शुरू करूँगा, जिस पर मेरे दोस्त सुजीत जी ने अभी बात की। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि ऐलोकेशन में रिक्रूटमेंट का हिस्सा क्या होता है? क्या वह आपके ज़ेहन में है भी या नहीं या आपने तय कर लिया है कि सब कुछ रोजगार विहीन ही होगा? 70 वर्षों से एक डिमांड, अहीर रेजीमेंट की डिमांड चल रही है, अभी भी गुरुग्राम में लोग बैठे हुए हैं। इनका एक गौरवशाली इतिहास रहा

है, यह आपके ज़ेहन में नहीं पड़ता, न पड़े। वोट की चोट बहुत सिखा देती है। मैं सिर्फ इतना कह कर अगले बिन्दु पर आऊँगा।

Sir, I am deliberately avoiding macro issues, I could have dealt with that-- poor health of economy, fiscal deficit, regressive taxation or K-shaped recovery. मैं बीते कुछ वर्षों से V-shaped, K-shaped recovery की बात सुन रहा हूँ, तो मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की। सर, एक Z-shaped recovery भी होती है, जो K के बाद 15वें alphabet के रूप में आती है। इस Z-shaped recovery में यह खतरा होता है कि आप पुनः recession में जा सकते हैं। आप ज्यादा अर्थशास्त्र समझते हैं, यहाँ से चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल जी बोले, आप Finance Minister हैं - आप लोग ज्यादा समझते हैं।

सर, हमारे लिए तो अर्थशास्त्र गरीब और निम्न आय वर्ग की थाली है। मैं तो उसका साइज़ देखता हूँ। बजट में पोर्ट वाले को क्या मिला, एयरपोर्ट वाले को क्या मिला, मैं उससे चिंतित नहीं हूँ। सब कुछ दे दीजिए, लेकिन गरीब की थाली महफूज़ रखिए। गरीब की थाली छोटी होती जा रही है, उसे नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी रेलवे वाले visuals आप सभी ने देखे होंगे। मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन और हेल्थ में जो allocation है, allotment है, उसमें एक बार फिर से रोजगार सृजन की कोई चर्चा नहीं है। There is no vision at all. आपने एक आंकड़ा दिया - 60 लाख पाँच वर्षों में! आपको लेबर फोर्स में एंट्री के लिए तैयार लोगों की फेहरिस्त की जानकारी है? करोड़ों-करोड़ दस्तक दे रहे हैं, आपने दरवाजे बंद करके रख दिए हैं, और चूँकि आपने दरवाजे बंद करके रख दिए हैं, इसलिए आपको वे visuals देखने पड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर एक रोजगार कैलेंडर पर काम करिए। सालाना - हर विभाग, हर क्षेत्र, हर निकाय, वहाँ से निकालकर रखिए कि कितनी वैकेन्सीज़ हैं और कब भरेंगे, क्योंकि जब तक आप उन वैकेन्सीज़ को नहीं भरेंगे -- माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सब्र का प्याला भरता जा रहा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी सदन में कहा है, हमारे प्रधान मंत्री जी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री बार-बार एक शब्द को कहते हैं - 'मुफ्त राशन', 'मुफ्त वैक्सीन' - मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हम वेलफेयर स्टेट हैं, 'मुफ्त' कहकर गरीब की गरिमा पर चोट मत करिए। हर नागरिक का स्टेक है और आप उस अधिकार के लिए कहते हैं कि 'मुफ्त' में दिया, 'मुफ्त' में दिया! आप बोरी पर अपनी तस्वीर लगा लीजिए, 'सोच ईमानदार, काम दमदार', वगैरह-वगैरह लिख लीजिए, लेकिन 'मुफ्त' कहकर गरीब का अपमान मत करिए, क्योंकि अगर गरीब की लानत पड़ेगी, तो बहुत मुश्किल होगी। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, Bryan Stevenson कहकर गए हैं - "गरीबी का विलोम संपत्ति नहीं होता है, गरीबी का विलोम न्याय होता है"। आपको अपने बजट के नजरिए में देखना होगा। मैं इस सदन में तीसरी बार बजट पर बोल रहा हूँ। Article 39 (c) एक बार पढ़िए और मूल्यांकन करिए "that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment;" Read the Oxfam report. **...(समय की घंटी)...** सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूँगा, थोड़ा ही लूँगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आप wind up कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, wind up ही कर रहा हूँ। सर, मैं यह कह रहा हूँ, मैं तीसरी बार यह आर्टिकल 39 दिखा रहा हूँ। खैर! सर, ग्रोथ की बड़ी चर्चा होती है। आप कुछ नंबर बताते हैं, ये इधर से dispute करते हैं। सर, हमें इससे भी मतलब नहीं है। आपकी ग्रोथ faceless क्यों है? Faceless growth, jobless growth और तब तुर्रा इस बात का कि five trillion dollar economy बनेंगे।

सर, आत्मनिर्भरता पर बहुत चर्चा होती है, मैं बोलना भी नहीं चाहता हूँ। मैं 'मनरेगा' को लेकर एक बात जरूर कहूँगा। कल सदन में सुशील कुमार मोदी जी बोल रहे थे कि आंकड़े में गलती की। उन्होंने Revised Estimate, का Budget Estimate का कहा। सर, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जब आपके पास Revised Estimates का आंकड़ा था और pandemic ने disruption कर दिया था, तो आपने उस आंकड़े को क्यों नहीं देखा, आपने उस आंकड़े को क्यों खारिज कर दिया? मैं आपको उस आंकड़े से संबंधित कुछ बताना चाहता हूँ। 'मनरेगा' में माँगने पर भी काम न मिलने में बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश सबसे ऊपर हैं। यह शर्म का विषय होना चाहिए, सदन के लिए सामूहिक शर्म का विषय होना चाहिए। यह पीठ ठोंकने की बात नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : अब समाप्त कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, मैं एकाध मिनट लूँगा, उससे ज्यादा समय नहीं लूँगा।

सर, हर साल काम न मिलने का औसत बढ़ता जा रहा है। आप pre pandemic 2018-19 से लेकर अब तक का देखिए। सर, मैंने अभी हाल ही में एक किताब पढ़ी। वह बड़ी अच्छी किताब है, मैं आपको भी दूँगा। मृणाल पांडे जी ने लिखी है - 'माया ने घुमायो'। सर, उसमें एक व्यक्ति कोरोना के काल में बहुत परेशान हो गया और उसे गाँव से निकाल दिया, तब वह एक कुएं के पास पहुंचा। उस कुएं में परियाँ थीं। उन्होंने कहा कि मैं दो शंख दे रही हूँ, जिनमें एक है करामाती शंख, जो मालिक को मनचाही चीज़ें देता है, एक है ढपोरशंख, जो लच्छेदार बोली बोलता है, बहुत देने का शोर मचाता है, पर वादे कभी पूरे नहीं करता।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : धन्यवाद। **...(समय की घंटी)...** आपका समय समाप्त हो गया है। अब समाप्त कीजिए।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, मुझे एक मिनट और दे दीजिए, sentence खत्म करने दीजिए। सर, अब मैं पूंजी निवेश के मामले पर आता हूँ। सर, मेरे कोई मित्र पूंजीपति नहीं हैं, उनका पूंजी से बहुत ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि निवेश के लिए क्या माहौल होना चाहिए। जहाँ फातिहा के लिए उठे हाथ पर controversy हो जाए, जहाँ वस्त्र, कपड़े, रहन-सहन और खान-पान पर controversy हो जाए, उस देश में अब कोई भी निवेश करने से हिचकेगा। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : धन्यवाद।

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, अभी 30 सेकंड्स हैं। **...(व्यवधान)..** सर, अब तो 'जय हिन्द' बोलने का समय आ गया है। मैंने शुरू में ही आपके लिए एक शेर सुनाया था, एक और शेर सुनाऊँगा। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : आप इतने समय तक बोल चुके हैं। **...(व्यवधान)...**

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, आखिर में मुझे rehabilitation पर बोलना है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : अब टाइम नहीं है। **...(व्यवधान)...**आज इसको खत्म करना है। **...(व्यवधान)...** The debate has to be concluded today. ...*(Interruptions)*...

प्रो. मनोज कुमार झा : सर, 30 सेकंड्स दे दीजिए। मुझे सैनिटेशन वर्कर्स माफ नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा था, manual scavengers के rehabilitation में self employment के लिए जो budgetary allocation होता है, उसमें आपने 30 परसेंट की कटौती कर दी। मैं अभी जब बोल रहा हूँ तो कोई न कोई manual scavenger किसी सीवर में अपनी आखिरी सांसें ले रहा होगा। सर, इसलिए मैं कहता हूँ और यह आपके लिए है:

"तेरे वादे पर जिये हम तो ये जान, झूठ जाना,
कि खुशी से मर न जाते ग़र ऐतबार होता।"

जय हिन्द!

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman Sir, in the extremely limited time at my disposal, I would like to confine myself to ...(*Interrruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, I have come to the 'Others'. You all have five minutes each because we have to complete the debate today itself. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: That's why, Sir, I am taking reference from my papers. I will try to finish as soon as possible. ...*(Interruptions)*... I will choose to confine my submissions only to the urban development component in the Budget 2022-23. As far as cities are concerned, we have a terrible scenario in our country -- polluted rivers, deteriorating air quality, dumps of garbage, huge deficit in basic amenities ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : वंदना जी, आप बैठकर भी बोल सकती हैं।

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Thank you, Sir, if you are able to listen to me, I am comfortable.

What we need is what the 'Habitat 2.0' called a revolution in urban problem solving. Nothing less will work. There have been studies in our countries, right from the time when the then Prime Minister, Late Rajiv Gandhi*ji*, set up the National Commission on Urbanisation to study the urban issues; in 2011, a High-Powered Expert Committee estimated the amount of investment; Committee of Experts in town planning pondered over what kind of manforce is required. There is latest report of reforms in urban planning capacity in India. All these documents spell out the urgency to address cities. And, on that count, I congratulate hon. Finance Minister, who seeks to steer a paradigm change to reimage our cities, only with a hope and prayer that this does not remain a false and half-hearted promise, like many others of the Government in the past.

Sir, the hon. Minister has spelt out several issues which I don't wish to point out because they are already in her Speech. But, I would like to make six suggestions for the Government's kind consideration.

One, I would like to suggest a National Commission on Urbanization and the constitution of State Commissions on Urbanization. We cannot forget that urbanization is a dynamic process and is continuously throwing us new challenges. It would be good if a statutory body in the form of a National Commission on Urbanization is constituted by legislation, which will continuously study and monitor trends of urbanization. Similarly, since local governance is a State subject, equivalent State Commissions for Urbanization should be constituted.

My second point is that there should be constitution of a special cadre for municipal services. Just like we have the Indian Administrative Services, the Indian Foreign Services, the Indian Revenue Services, there should be a separate cadre for municipal services. It is absolutely required, considering the fact that municipal corporations now require urban planners, economists, management personnel, ecologists, geologists, experts on water and environment. All these are missing at the moment.

My third point is about the encouraged public participation. In order to make our cities livable, efficient, productive, sustainable, resilient, inclusive, people-centric, and techno-savy, we need experts from different fields to understand the knowhow.

My fourth point is this. Urban land issues, social and natural features, need to be taken into consideration. Land is one of the most important resources in every city. And, there is need to address urban land issues beyond real estate.
There is a need to address urban land issues beyond real estate so as to address equity, disparity and inclusion, and also for the protection of natural features, water bodies and biodiversity.

Point number five is, setting up of an urban employment guarantee scheme on the lines of MNREGA. We have seen the plight of migrant workers and the urban poor during the lockdowns. Schemes for the urban poor on the lines of MNREGA will greatly help to address the issues of joblessness and unemployment. Services such as arrest of degradation of environment, plantation and conservation of trees and programmes like Swachh Bharat Mission could, definitely, be a part of this.

My last point is, mandate annual reports on the status of environment from the ULBs; and, further mandate preparation of plans for climate change, its mitigation and adaptation. Several Members have mentioned how the cities got impacted by torrential rains and storms. In this respect, I wish to draw the attention of the Government to Schedule XII of the 74th Amendment, which says that protection of environment, promotion of ecological aspects and urban forestry are responsibilities of the Municipal Corporations. However, there is no mechanism to monitor what they are doing. Therefore, I urge the hon. Minister to make certain budgetary provisions for local governments which have paucity of funds to make sure that they can do this. I would also say that this could amount to be your first step, Madam, in making the urban development meaningful and also a first step in the creation of awareness in the direction of enhancing the understanding of carbon neutral cities.

To conclude, we are aware that cities are engines of growth. Cities occupy onlythree per cent of the nation's land but their contribution to the GDP is a whopping 60 per cent. This is expected to rise to 75 per cent by 2030. To realise our goal of a 'five trillion dollar economy' by 2025 and for the 'job creation' for our youths, our cities will have to be strengthened, strengthened 'sustainably' with 'its people' at the centre. As someone has rightly said, "cities have the capability of providing something for everybody, only because and only when they are created by everybody." In conclusion, the rate at which our cities are growing, the rate at which they are deteriorating, I consider this as our last chance. Our cities are not just in the ICUs, they are on ventilators. Therefore, we cannot afford to go wrong. Thank you, Sir, for giving me the opportunity.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Ajit Kumar Bhuyan. Please take the example of your previous Member; she finished within time. You have five minutes.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN (Assam): Sir, I will try my best. Mr. Vice-Chairman, Sir, the legendary lawyer, who was also an economist by choice, while analysing the Union Budget once said, "After all, a Budget is not intended to be merely an exercise in political survival or an essay in political gimmick, it is intended to equip the country to face the grim realities of the economic situation." What are the economic realities of this country today? Are there any genuine attempts by this Government through the Budget to equip the country to face the grim realities of economic inequality? My emphatic answer would be 'No'. The Union Budget, 2022-23, has not taken cognizance of the needs of the poor and the middle class despite compelling evidence of widening inequalities. According to the World Inequality Report, 2022, India stands as one of the most unequal countries in the world with widespread poverty alongwith an affluent elite. The Report points out that in 2021, the top 10 per cent held 57 per cent of the total wealth in the country while the share of the bottom 50 per cent was just 13 per cent in the national income in 2021. The Oxfam India's Report on inequality finds that the richest 98 Indians own the same wealth as the bottom 552 million people. The Covid-19 pandemic has brought income inequality with 84 per cent of Indian households witnessing a decline in their incomes. The Oxfam report also points out that the number of billionaires in the country increased from 102 to 142 during the pandemic period even as more than 4.6 crore Indians fell into extreme poverty in 2020.

Sir, I now want to raise certain points related to Assam. The State of Assam, which I am representing, is lagging far behind in industrial growth. Industrial development is necessary for the overall development of the State as well as for the generation of employment opportunities for skilled and unskilled workers.

In 2018 in the name of industrial development, '"Advantage Assam" was pitched with much fanfare but it ended in a cloud of smoke without tangible results. Grabbing of Government incentives and preferences meant for the industrial development of North-East by some vested interest lobbies be prevented. The need of the hour is some concrete steps for the development of industrial sector in Assam but the same is not visible in the Budget.

The power scenario of Assam is very pathetic. Sir, against a demand of around 2,000 MW, the State generates only around 250 MW and is vastly dependent on Central allocation. Assam was a pioneer in the country in setting up gas-based

power stations in the 60s in the form of Namrup Thermal Power Station. Now in the fitness of things, set up a gas-based super thermal power station in between Kokrajhar to Kamrup by utilizing gas from the National Gas Grid which is now under construction.

Sir, which major projects have been conceived and initiated by the Modi Government in the last seven-and-half years in North-East States and Assam in particular?

Sir, has the DoNER Ministry taken the initiative to explore major projects with the Finance Ministry in the sector like solar energy?

Tea and oil have been two important assets of Assam, and in the above-mentioned sectors, what has the Modi Government done to generate employment for local people?

The North-Eastern States had been enjoying special status but Modi-led Government discontinued it. Has the Government of India taken corrective measures to bring North-Eastern States to a sustainable level as all North-East States have been facing acute financial crisis?

Will the Finance Minister enlighten the House on what is the total earnings from Assam in the oil sector per year and the royalty payoff to Assam? ...*(Time-bell rings)*... Sir, just one minute.

With the introduction of GST, the State Government is left with little flexibility in generating its own resources. The State is reeling under a severe financial crisis which impeded developmental activities. One of the importance sources of revenue for the State is royalty from crude oil. Although royalty is required to be paid on the last date of each month as per the Petroleum and Natural Gas (Amendment) Rules, 2003, it has never been done. Moreover, the amount of royalty is 20 per cent of the crude price which has not been revised for long. This amount is too small.

Sir, I now want to raise two-three points related to North-Eastern Region.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: The Prime Minister's Development Initiative for North-East has been highlighted by the Finance Minister in her Budget Speech. Will this initiative with a budgetary provision of Rs. 1,500 crores address any core issues and concerns of distressed youth of North-East States? The Act East Policy is just a slogan as no concrete Action Plan has been formulated to make the region a hub of export centres with the border countries.

At last, conceived in place of Seven Sisters by the Prime Minister during his visit to the region, I am wondering what is a special component except the Prime Minister's expertise in coining slogan and nothing else!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you.

SHRI AJIT KUMAR BHUYAN: Sir, just two lines. I would like to conclude by requesting the Government, please do not play with *jumla* and slogan with the North-East people, especially, the youth, as the region has been in political conflict because of geographical location.

The Union Budget is a good weapon to create confidence in future in the mind of people but, sorry to say, no such attempt has been made in that direction. Thank you.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Sir, while presenting this year's Budget, the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharaman, said that since India was celebrating *Azadi ka Amrit Mahotsav* and has entered into *Amrit Kaal*, the Government has aimed to attain the vision of our hon. Prime Minister, and this Budget would pave the way to achieve its desired goals in the near future, thus making India a five trillion dollar economy. But the fact is that the expectations and hopes of the common people have been belied completely in this Budget. Amid rising unemployment, inflation and falling incomes, which caused uneasiness among the common people, though this situation got aggravated due to the Covid pandemic, nonetheless this Budget has left the poor people high and dry. Rosy pictures drawn in the earlier budgets are far from realization and yet another new dream is being shown to the people who are expecting *achche din*, hoping against hope. The stark reality is that the rich have become richer while the poor have become poorer.

Sir, ours is an agrarian economy. Though the agriculture sector has been allocated quite a bit in this Budget, the budgetary provisions about rural development, especially MNREGA, have been reduced. This will not only create difficulties in the development of the rural areas, but would also affect the various schemes being implemented for farmers through MNREGA. The provision made in this Budget for MNREGA would provide hardly 30 days of employment instead of 100 days of employment that is stipulated in this scheme.

Sir, we cannot forget the contribution of the farming community that produced record grains during the Covid pandemic and immensely supported our economy during tough times. Therefore, the agriculture sector should have been allocated

more funds than what has been provided for in this Budget. Similarly, the agro-processing industry needed greater thrust than the provisions that have been made. Creation of employment in the agro sector is the need of the hour and, therefore, the Finance Minister should have considered this aspect in order to boost the rural economy. Unless these issues are addressed on a priority basis, doubling of the farmers' income would also remain a distant dream.

Sir, the allocation made in the healthcare sector should have been much more than last year as the strengthening of health infrastructure is of essence. However, schemes introduced in this Budget, like *Ayushman Bharat*, Digital Mission and National Mental Health Programme in the health sector were necessary and are laudable. The 'One Class One TV Channel' programme under PM e-Vidya would be extended from 12 to 200 channels. This initiative to impart quality education to our children, particularly in rural areas, and those from SC, ST and other weaker sections is a welcome step. But the overall budgetary provision in the education sector should have been in the range of around three per cent of the GDP, which is, unfortunately, just one per cent in the present Budget.

Sir, under the head 'housing for all', an objective of building 80 lakh houses for identified eligible beneficiaries of PM *Awas Yojana* has been set and Rs. 4,800 crore have been allocated for this purpose. The hon. Finance Minister has desired that private developers participate in building affordable housing, which also has a huge potential for employment, but the purchasing power of the people is a million dollar question, because people have lost their jobs, people have suffered heavy losses on their small businesses during the pandemic and, at the same time, the real estate industry has been performing at its lowest since the onslaught of Covid-19. Although banks have been recapitalized substantially, there is still lukewarm response to the credit off-take. The Government should devise special schemes to give a boost to the real estate sector. Else, housing for all by 2022 will also turn out to be a hollow promise.

Sir, the impact of the Covid pandemic on the MSME sector was so bad that in the last two years, several small and medium units faced closure due to heavy losses during lockdown and consequently, retrenchment of workers, which brought several families on the roads. Emergency Credit Line Guarantee Scheme definitely gave the much-needed support to this sector to make a comeback and regenerate employment, but all is not well yet. The MSME sector does need more support from the Government by way of unrestrained lending through the banks and NBFCs, as this sector is one of the largest contributors to the GDP of our country and also a job creator. Sir, the focus of the Government in this Budget on creating modern

infrastructure is another big promise. However, the success of the infra build-out, especially where PPPs are being visualised, will depend on the schemes being properly framed. National Infrastructure Pipeline and Gati Shakti Programmes sound good but need effective implementation. The Government should make the terms and conditions of the projects attractive enough to entice the private sector to implement them. Hon. Finance Minister has said in her Budget Speech that public investments would need to be complemented by private capital on a significant scale. Therefore, this will materialise only if projects are remunerative for the concessionaire, else, these mega projects will not gather the required momentum and the targets will not be achieved.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now.

SHRI ANIL DESAI: The outlay for the Scheme for Financial Assistance to States for capital investment which has been enhanced to Rs.15,000 crore and also provision of Rs.1 lakh crore to assist the States in catalysing overall investment in the economy would be meaningful only if these loan facilities are free of onerous conditions; or else, the States will not get any benefits from this enhanced limit. Sir, under the leadership of hon. Chief Minister, Shri Uddhav Thackeray, with the help of Maha Vikas Aghadi Government, my State of Maharashtra has taken so many measures that Maharashtra is on the progressive path and has still retained No. 1 position in the country, irrespective of whether we get the support from the Centre or not.

The middle class had hoped that hon. Finance Minister would give the small tax payers some relief and provide extra support to small businesses. It was also expected that the tax rates would be raised for large corporates who are doing extremely well. The Government chose to favour the corporates, but the middle class which is battling the soaring inflation and high medical expenses is left disappointed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude now.

SHRI ANIL DESAI: Sir, allow me to state one or two points. Announcements made by the Government in the earlier years about creation of two crore jobs every year has come down to creating sixty lakh jobs in this year's Budget. Dismantling of profit-making public sector will certainly impact the employment scenario very badly. Disinvestment in LIC, privatisation of nationalised banks, sale of BPCL and Pawan Hans will have a bad impact on the economy. It is surprising that on the one side the Government is doing away with its ownership in public sector and, on the other hand,

investing sizeable capital to support the Vodafone Idea venture in private sector. It is unfortunate that Government-owned General Insurance Companies' employees numbering around one lakh have not yet got their upward wage revision which is pending for last five years. In every meeting with the management and the Government, the poor employees are only promised of early settlement but no action is taken on their rightful dues. I would urge the hon. Finance Minister to award these employees their wage revision at the earliest.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please conclude.

SHRI ANIL DESAI: Sir, I am making the last point. The GST collection in January this year was more than Rs.1.40 lakh crore, but the hon. Finance Minister did not announce any benefit out of this to the States. Also the States had demanded to extend the five year period of GST compensation which is ending this year by another three years but the Budget is silent on it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Your time is over. I am calling the next speaker.

SHRI JOSE K. MANI (Kerala): Sir, due to paucity of time, I will confine myself only to two points as most of the points have been discussed by my colleagues. One point is about the Covid and the health care and the second point is about agriculture and farmers. Covid-19 pandemic has showcased the inability of the Central Government. The pandemic has brought visibility to the country's health infrastructure and the need to increase Government's spending on public healthcare to, at least, 0.5 per cent of the GDP as recommended by the National Health Policy of 2017. India's public health spending as share of GDP is the lowest among the BRICS nations. While the Government is praising the schemes and policies introduced to improve the condition of farmers in the country and the positive growth witnessed by the agriculture sector last year, the Government is silent about the issue of the farmers and agriculture labour suicides still prevalent in the country. According to the data released by the NCRB, suicides in the farming sector in the country increased in the year 2020 as compared to 2019. The Budget has not touched the millions of Indians who have got adversely affected due to Covid. As many of my colleagues have said, the gap between the haves and the have-nots has widened. The haves have become richer, but the have-nots have become poorer. There is no real freedom without economic freedom, and the way the nation's income and expenditure has been allocated, it has

resulted in increase in the number of the poor, especially among the farmers. The Covid pandemic has affected the nation and all the strata of people, but when you go through the statistics, you will find that it has mostly affected the farmers who feed us. The maximum people who have died due to Covid are also the farmers. Now, the farmers are facing the provisions of the SARFAESI Act, these are being mercilessly imposed by the banks. Here, I request the Government of India to take necessary steps. At least, the government should take the first step to waive off all the agricultural loans which were taken by the farmers who have died due to Covid, who were the bread earners of their families. I request the Government of India to provide a special package for the ordinary workers who are facing great difficulty in finding jobs during the Covid times.

Regarding Kerala, I would like to say that the backbone of Kerala's economy depends on the rubber farmers and the price of rubber. I am specifically raising this point mainly because our rubber farmers are in distress. The Finance Minister was in charge of the Commerce Ministry earlier. She knows the plight of the farmers. She had come to Kerala and had interaction with the rubber farmers and other stakeholders. So, she really knows the plight of the rubber farmers. That is why, I wanted to talk about the rubber farmers here. I had taken up this issue in the Zero Hour also. The fall in the price of natural rubber is mainly due to dumping or import of natural rubber. Recently, the Competition Commission of India had fined five leading tyre manufacturing companies to the tune of Rs.1,788 crores. Why were they fined? They were fined for forming a cartel and purposely and deliberately reducing the price of natural rubber. If the price of natural rubber goes down, the price of tyre also goes down. At the same time, they had decided to increase the price of tyre. Who are the victims in all this? The victims are the poor farmers. These companies have been fined only for one year. God knows what they have done during all these years from 2005 onwards, for the last one decade. But, the Competition Commission of India got the evidence only for one year. The poor farmers are facing a lot of problems because of this fall in the price of natural rubber. It has not only affected the farmers, but the people of India, who own a vehicle, are also the victims because artificially, the price of tyre has also been increased. *(Time bell rings)* Sir, I will take only two minutes.

Now, my request to the Government of India is that if we need to increase the bound duty, the rubber should be declared as an agricultural produce. We should also have a mechanism to calculate the cost or production every year and a Minimum Support Price of Rs.250 per kilogram for natural rubber should be provided from the start. Lastly, I request the Government of India that the fine of Rs.1,788 crores

collected from these companies, which belongs to the farmers, should immediately be given to the farmers, taking into consideration the fact that a Minimum Support Price of Rs.250 per kilogram should be given to the poor farmers initially. Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): श्री राम नाथ ठाकुर जी, आप बजट चर्चा पर बोलिए, आप बैठकर भी बोल सकते हैं।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 की चर्चा पर बोलने के समय दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बात कहना शुरू करता हूं।

महोदय, मैं बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत सरकार ने पंजाब से बंगाल, वाया गया, बिहार 16 सौ एकड़ जमीन सेलेक्ट की है, जिसमें इन्होंने उद्योग के लिए प्रोविज़न किया है। अगर यह काम इस वित्तीय वर्ष में शुरू हो जाता है, तो बिहार, जो कि बेरोज़गार है, जहाँ उद्योग-धंधे नहीं हैं, वहाँ उद्योग-धंधे लगने के बाद लोगों में जागृति पैदा होगी, उद्योग-धंधे बढ़ेंगे और मैन्युफैक्चरिंग होगी। जब बड़े उद्योगों के साथ छोटे-छोटे उद्योग भी लगने शुरू हो जाएंगे, तो इससे बिहार की प्रगति और उन्नति होगी, इसलिए हम भारत सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं।

महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि बिहार में कृषि, पशु-पालन, मत्स्य पालन, सब्ज़ी उत्पादन, फल उत्पादन और मसाला उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। बिहार के दरभंगा जिले में उत्तम कोटि का मखाना पैदा होता है, इसलिए इस व्यवसाय को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। मुजफ्फरपुर की शाही लीची संबंधित व्यवसाय उद्योग के रूप में उत्तर बिहार में लगना चाहिए। प्रत्येक जिले में फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इससे रोज़गार मिलेगा। बिहार के समस्तीपुर जिले में तंबाकू और हल्दी का उत्पादन होता है, इनका भी मसाले के रूप में कारखाना लगना चाहिए। बिहार में एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हमारे रक्षा के क्षेत्र में बिहार में 'रक्षा गलियारा' का निर्माण कराया जाए, जिससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बिहार को लाभ हो। हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया है। बिहार में उत्तर बिहार के 28 जिले नेपाल के कारण बाढ़ग्रसित होते हैं, जबकि दक्षिण बिहार में 10 जिले सूखाग्रस्त होते हैं। बिहार की सरकार ने उत्तर बिहार की नदियों को दक्षिण बिहार से जोड़ने का प्रोजेक्ट बनाया है। भारत सरकार उस पर प्राथमिकता देने का काम करे, जिससे बिहार में आर्थिक गतिविधि बढ़ सके।

महोदय, मैं 5वीं बात कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को जातीय गणना करानी चाहिए। छोटी-छोटी जातियों की क्या समस्याएं हैं, उनका क्या रूप है, इसे जानने के लिए जातीय गणना करानी चाहिए और इसे भारत सरकार को इस बजट में लाना चाहिए - यह मेरी मांग है।

महोदय, मेरी जो एक दूसरी अन्य मांग है, वह यह है कि 2022-23 के वित्तीय बजट में 25 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवेज़ और सड़क बनाने का काम शुरू किया गया है। बिहार में कहाँ-

कहाँ, किस-किस जिले में यह प्रोजेक्ट शुरू होगा - हम इसको जानने की भारत सरकार से मांग करते हैं। भारत सरकार ने हवाई अड्डे को भी विकसित करने का काम शुरू किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने बिहार में किन-किन हवाई अड्डों के लिए मांग रखी है, इसमें किन-किन जिलों को सेलेक्ट किया है? हम इसकी भी मांग करते हैं कि बिहार में हवाई अड्डा बनना चाहिए और जिस जिले में हवाई अड्डा नहीं है, उस जिले को भी इसमें शामिल करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अदालत में 76 परसेंट विचाराधीन कैदी वर्षों से पड़े हुए हैं। इस वित्तीय वर्ष में इस बजट में कहीं भी उन्हें छोड़ने के बारे में नहीं कहा गया है। धारा को कम करके, जिनकी उम्र 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष हो गई है, उनको छोड़ने के लिए इस बजट में प्रावधान होना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... महोदय, बजट में रेलवे के बारे में जो ज़िक्र आया है, इसमें 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात कही गई है। हम माँग करते हैं कि इन 400 नई वंदे भारत ट्रेनों में बिहार में कौन-कौन सी ट्रेनें दी गई हैं, बिहार को रेल की कौन-कौन सी सुविधाएँ दी गई हैं, इसका विवरण भी इस बजट में देना चाहिए। मैं वर्षों से, कई बार से यह माँग कर रहा हूँ कि जहाँ ओवरब्रिज की जरूरत है, वहाँ ओवरब्रिज बनना चाहिए और जहाँ नई ट्रेन खुलनी चाहिए, बिहार से दिल्ली के लिए, चेन्नई के लिए, मुम्बई के लिए, वहाँ से चालू करनी चाहिए। वर्षों से हमारी यह माँग रही है। महोदय, हम एक नई बात कहना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : आप समाप्त कीजिए।

श्री राम नाथ ठाकुर : सर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। हम यह कहना चाहते हैं कि किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन पर प्रकृति की भी मार पड़ रही है। आपने इस वित्तीय वर्ष में 'मनरेगा' का पैसा कम कर दिया है। लोगों को, किसानों को, मजदूरों को फायदा होना चाहिए, इसलिए 'मनरेगा' का पैसा बढ़ना चाहिए और इसमें गरीबों के लिए रोजगार मिलना चाहिए। किसी रचनाकार ने कहा है कि:

"है पेट जहाँ खाली नर का,
उस घर में दीप जलेगा क्या?
जब घास न कोई देता है,
तो बूढ़ा बैल चलेगा क्या?"

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : धन्यवाद।

श्री राम नाथ ठाकुर : सर, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। सर, 2021 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में चार प्रदेश सबसे पिछड़े हैं - मध्य प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। इसलिए नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इसको विशेष दर्जा देने की माँग को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को विशेष दर्जा देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आरज़ू करना चाहता हूँ कि भारत सरकार मेरी बातों को सुने और

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का काम करे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिन्द, जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : धन्यवाद। श्री एम.वी. श्रेयम्स कुमार।

SHRI M.V. SHREYAMS KUMAR (Kerala): Sir, the Finance Minister speaks about *'Amrit Kaal'*, describing about India at 100. Mahatma Gandhi has said, "The future depends on what we do in the present." A future plan of *'Amrit Kaal'* without addressing the challenges of the present is pointless. This Budget turns a blind eye towards the struggles of millions of Indians affected by the pandemic. The Finance Minister speaks about *'Gati Shakthi'*, ignoring the *durgati* of the *aam aadmi*. Sir, year on year, this Government has reduced the allocation for MNREGA. This year, there is a reduction of 26 per cent. From the last year's Revised Estimate of Rs. 98,000 crores, we have come to Rs. 75,000 crores. At this rate, the largest employment programme in the world will come to a standstill. If this is any indication, the next Budget will be the last nail in the coffin of MNREGA. The Budget Speech does not even mention about MGNREGA. The Finance Minister quotes from the *Shanti Parva* chapter of the *Mahabharata* and speaks about the arrangements for *Yogakshema*. It is a paradox that the Government has kept for sale the LIC whose motto is *Yogakshemam*. By keeping it for sale, the Finance Minister has actually snatched the proclaimed purpose of *Yogakshemam* from the LIC.

The Government is taking revenge on farmers for their victorious struggle by reducing the share of agriculture and allied activities in the total budget from 4.3 per cent last year to 3.8 per cent this year. The Prime Minister declared in February 2016 that in six years they will double the income of farmers. But so far it has not happened. We have reached 2022, and there is not even a mention about this by the Finance Minister.

The Budget Speech mentions about procurement of paddy and wheat alone. The number of benefitted farmers in 2021-22 has fallen by 17 per cent, and the quantity procured has decreased by seven per cent from 2020-21.

We see reduced allocation of Rs.500 crore in the Crop Insurance Scheme -- from Rs.16,000 crore to Rs.15,500 crore. There is reduction of Rs.2,095 crore for the Market Intervention Scheme and Price Support Scheme -- from Rs.3,595 crore to Rs.1,500 crore.

When the entire lower and middle class is struggling with the inflation and economic crisis during the pandemic, the Government has not taken any steps to revise the income tax slab for the salaried people. The Budget failed to provide any kind of respite, leaving them to suffer in these difficult times.

There is a reduction of Rs.34,900 crore in fertilizer subsidy from the Revised Estimates of Rs.1,40,000 crore to Rs.1,05,000 crore. There is a reduction of Rs.79,638 crore in food subsidy from the Revised Estimates of Rs.2,86,000 crore to Rs.2,06,000 crore.

The country is still grappling with COVID and its new variant, Omicron. Instead of offering solace to the common man, the Government has drastically cut down on fertilizer and food subsidies without any rhyme or reason.

There is zero allocation towards "India COVID-19 Emergency Response and Health Systems". Last year's allocation was Rs.12,359 crore. This action of the Government creates an impression that the pandemic is no more a priority.

Even though the focus on mental health in this Budget is commendable, the Union Budget 2022-23 has given the cold shoulder to the Indian medical device industry. Overall, the proposals made in the Budget 2022-23 should have made quality healthcare accessible and affordable.

Long time demands of Kerala such as Trivandrum-Kasargod Semi-High Speed Rail Project, setting up of All India Institute of Medical Sciences, and Sabari Rail Project were once again ignored in this year's Budget too. The long-pending demand for special railway zone for Kerala is again overlooked by the Central Government.

Natural rubber growers and coconut farmers are totally ignored. My colleague, Mr. Jose K. Mani, has raised that issue here.

There is a reduction of Rs.90 crore for the allocation to the Ministry of I&B from Rs.4,071 crore to Rs.3,980 crore. There is a reduction of Rs.30 crore in information and publicity from Rs.971 crore to Rs.942 crore which will affect the media industry adversely. Newspaper industry in the country is going through a major crisis. I request the Minister to withdraw the five per cent duty levied on the newsprint.

I congratulate the Government for allocating Rs.3,965 crore to the MPLAD Scheme. It is a welcome step. I congratulate the Government. I also urge the Minister to increase the allocation from Rs.5 crore to Rs.10 crore.

Last year, India performed poorly in various global indices that reflect quality of life, human capital or human development in the country such as the Human Development Index (rank 131 out of 189 countries) and the Global Hunger Index (rank 101 out of 116 countries). This Budget fails to acknowledge and address these critical issues with genuine prudence.

With this, I stand to oppose the proposals of the Union Budget, 2022-23.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA) : You still had one minute. Anyway, thank you. श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी, आपकी पार्टी ने आपको 11 मिनट दिए हैं, तो आप समय पर अपनी बात समाप्त कीजिए, नहीं तो बाकी लोगों को समय नहीं मिलेगा।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, पहले तो मेरा समय कम करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे पार्टी ने 15 मिनट बोलने के लिए कहा था, लेकिन अब आपने मेरा समय कम कर दिया है, तो आपको तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता) : आपका समय कम हो गया है, लेकिन मैं समय कम नहीं करता हूं, पार्टी करती है।...(**व्यवधान**)... नहीं, नहीं, आप उनको बोलने दीजिए, आप बैठिए।...(**व्यवधान**)...

1.00 P.M.

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह: महोदय, मैंने अपने पूरे संसदीय जीवन में विधान सभा में काम किया, लोक सभा में काम किया और अब मैं राज्य सभा में हूं। इस दौरान मैंने एक दर्जन से ज्यादा बजट पास होते हुए देखे, लेकिन इतना निस्तेज और निरुद्देश्य बजट मैंने आज तक नहीं देखा। पिछले दो सालों से पूरा देश कोरोना के संकट से जूझता रहा और मुझे ऐसा लगता है कि यह बजट भी कोरोनाग्रस्त हो गया है, इस बजट को भी लकवा मार गया है। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, पूरा देश कुछ उम्मीद कर रहा था। इससे पहले भी हम लोग यह देखते रहे हैं - यूपीए-1 में मैं मंत्री था और मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि अपने पहले बजट भाषण के समय जब चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे, तब उन्होंने दो-तीन घोषणाएं की थीं कि हमारी सरकार रूरल क्रेडिट को दोगुना करेगी, किसानों के एमएसपी को हम दोगुना करने का काम करेंगे और अपने अंतिम बजट में उन्होंने रूरल क्रेडिट न केवल दोगुना किया, बल्कि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे तिगुना करके देश को दिखाने का काम किया। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का मुद्दा है, उस पर इतना बड़ा आंदोलन देश में हुआ, शायद आज़ादी के बाद का यह सबसे बड़ा किसान आंदोलन था, जिसे देश ने देखा है। जब मोदी जी की सरकार तीन बिल लाई थी तो उन लोगों की क्या मांग थी - उनकी मांग थी कि आप एमएसपी पर कानून बनाकर दें, कानून की गारंटी से एमएसपी लायें। लेकिन वह तो नहीं हुआ। अभी आपको तीनों काले कानून किसानों के दवाब के आगे वापस लेने पड़े या पांच राज्यों में जो चुनाव होने थे, उसकी वजह से वापस लेने पड़े या फिर जो बाई-इलेक्शन के परिणाम आए, उसमें आपकी पार्टी की जो हार हुई, उसकी वजह से आपने कानून वापस लिये, लेकिन किसानों को आश्वासन देने के बाद भी कोई कानून नहीं बना।

महोदय, मैंने बजट में जो देखा है, यदि इस बजट में कृषि क्षेत्र की बात करें तो महत्वपूर्ण योजनाओं के बजट आवंटन में भी कमी की गई है। एक ओर प्रधान मंत्री जी हर भाषण में 'फसल बीमा योजना' का हवाला देते है। 'फसल बीमा योजना' में भी पिछले साल के मुकाबले बजट लगभग 500 करोड़ रुपया कम कर दिया गया। देश में एमएसपी को लेकर जो संशय की स्थिति थी, वह कमी दूर नहीं हुई। 'प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान' और 'पीएम-आशा'

आजकल यह परिपाटी बन गई है कि जो भी नई स्कीम आती है, उसमें एक प्रीफिक्स और सफिक्स प्रधान मंत्री जी के नाम से लग जाता है। यह जो स्कीम है, वह भी एमएसपी आधारित व्यवस्था का हिस्सा है और पिछले साल इस स्कीम में एक्चुअल खर्च चार सौ करोड़ रुपये था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस साल इसमें केवल एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे मुझे यही लगता है कि सरकार की मंशा 'पीएम-आशा योजना' बंद करने की है, जब वित्त मंत्री जी उत्तर देंगी तो उन्हें इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

इसके अलावा 'मनरेगा' यूपीए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी। प्रायः सभी सहयोगी साथियों ने जब कभी अपना भाषण किया है तो सबने चर्चा की है कि उसमें भी कमी की गई - उसे आपने 95 हज़ार करोड़ रुपये से घटाकर 71-72 हज़ार करोड़ रुपये कर दिया। गांवों में, खासकर कोरोना काल में अगर गरीब लोग बचे रहे तो वह स्कीम एक ढाल के रूप में गरीबों के लिए खड़ी थी और उससे बहुत कुछ बचा रह गया।

कोरोना में लोगों को टीका लगाना, यह लगता है कि यही इस सरकार का सबसे बड़ा प्रमुख अस्त्र है। अर्थव्यवस्था खराब है, उसके बारे में कुछ नहीं करना है, लोगों का रोजगार गया, उसके बारे में कुछ नहीं कहना है, प्रायः सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई-लिखाई, पठन-पाठन ठप हो गया है - मैं एचआरडी सबंधी संसदीय स्थायी समिति का सदस्य हूं, उसकी मीटिंग्स से पता चलता है कि बच्चों में किस तरह का learning loss हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है। 'PM eVidya Scheme' आदि सब कुछ digital होता जा रहा है, लेकिन आपको साथ-साथ यह भी करना चाहिए था कि इसमें जो digital fraud हो रहा है, जितना इससे transaction हो रहा है, उसमें आप और हम जीवन में कभी न कभी fraud के शिकार होते हैं और पूरा देश शिकार होता है। उस पर आप कुछ कहते नहीं हैं, उसके लिए आप कोई कानून नहीं लाते हैं। तो जिस तरह का यह बजट है, उसमें आम लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। आज आम आदमी हताश और निराश है और जिन लोगों के लिए बजट है, प्रधान मंत्री जी के मित्रों के लिए - कल ही कपिल सिब्बल साहब ने अपने भाषण में बताया कि 142 billionaires की Income कितनी बढ़ी, लेकिन इस पर सरकार का ध्यान नहीं है कि जो 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गये, 'अंत्योदय अन्न योजना' और बीपीएल परिवार की श्रेणी में जो चले गये, उनके लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़े। जो तीन करोड़ लोग middle class से नीचे चले आये, उनके लिए टैक्स में कोई रियायत क्यों नहीं दी गयी, इस पर आपका बजट प्रायः चुप है और आपके मित्र जब उधर से बोलते हैं तो जो बात suit करती है, वही बोलते हैं। हम देख रहे थे कि जब अरुण सिंह जी ने अपना भाषण शुरू किया तो वे आईएमएफ के एक डायरेक्टर का हवाला देते हुए बजट की तारीफ करने लगे, लेकिन जब कोई और प्रतिष्ठित international agency या अखबार कोई आलोचना करता है, तो वह आपको प्रायोजित लगने लगता है। New York Times की एक रिपोर्ट थी। New York Times आपके बजट के बारे में कहता है कि "A large share of the government's spending will be raised from borrowing and taxes, including those on fuel and fertilizers, which have contributed to rising prices of food and essential commodities. Another major concern for economists is the Government's attempts to keep its deficits in control by reducing the spending on social schemes and welfare." यह हकीकत है। इसे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते और कैसे कीजिएगा, यह deficit आयेगा

कहां से? कहने के लिए तो 'Make in India' है लेकिन हो यह रहा है कि सब कुछ sell in India में जा रहा है। आजादी के बाद हमारे पुरखों ने जो संपत्ति अर्जित की थी, भिन्न-भिन्न पब्लिक सेक्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट था, हमारे पुरखों की वह सारी संपत्ति बेची जा रही है और यही आपकी इन्कम का सबसे बड़ा स्रोत है। मैंने एड़ी उठा-उठाकर देखा कि प्रधान मंत्री जी उस दिन भाषण कर रहे थे और उसमें कांग्रेस पार्टी को कोस रहे थे। प्रधान मंत्री जी, आप ही कभी-कभी बात करते हैं कि यहां डिबेट का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। अगर खरगे साहब चंद सवाल खड़े करते हैं, आनन्द शर्मा जी चंद सवाल खड़े करते हैं, जो कि आम लोगों की समस्या है, आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या है, तो उस पर जवाब देने के बजाय आप कांग्रेस पार्टी को गाली देने लगते हैं। यह कहां का न्याय है? यह देश किसानों का है, यह बात आप सबको समझने की जरूरत है। जब देश में अनाज की कमी थी, तब Green Revolution हुआ, उस समय तो आप हुकूमत में नहीं थे, बल्कि काँग्रेस पार्टी हुकूमत में थी और इन्दिरा जी के step से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। आज मनोज जी ने ठीक कहा कि आज गरीबों की थाली से दाल गायब है, सब्जी गायब है।...(**समय की घंटी**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please wind up....*(Interruptions)*...

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : सर, आप तो इधर से ही गए हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं?

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : कृपया आप wind up कीजिए।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : सर, जो अच्छी बात है, उसको सुनिए और उधर बताइए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि चूँकि आपका समय हो चुका है, इसलिए अब आप wind up कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो बाकियों को समय नहीं मिलेगा। आपकी पार्टी से और भी स्पीकर्स हैं। अगर बाकी स्पीकर्स sacrifice करते हैं, तो यह अलग बात है, लेकिन अभी आपकी पार्टी से दो स्पीकर्स और हैं, जिन्हें अभी बोलना है, इसलिए आपको उनके लिए भी समय बचाना है।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : सर, आप तो ... (**व्यवधान**)... आप थोड़ा-सा नीचे की तरफ देखिए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : सर, मैं बिहार से आता हूँ। वहाँ पर आपकी पार्टी सरकार में है। सुशील कुमार मोदी जी चले गए, जब तक वे बिहार में थे, तब तक वे अच्छे नेता थे, लेकिन आपने उनकी ऐसी स्थिति कर दी कि वे भी बजट पर भाषण करते-करते कवि बन गए और कविता कह कर अभी बाहर हैं। मैं उनको सुनाने वाला था। बिहार पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में best administered State के रूप में जाना जाता था। उस समय वहाँ पर काँग्रेस की हुकूमत थी।

देश जितनी चीनी पैदा करता, उसकी 27 परसेंट चीनी बिहार पैदा करता था। अब आपकी हुकूमत में यह 27 परसेंट से 2 परसेंट पर चला गया। वहाँ के समाजवादी मुख्य मंत्री, जिनको कल ही प्रधान मंत्री जी ने कहा कि वे, यानी नीतीश कुमार जी अच्छे समाजवादी हैं, लेकिन आप उनकी बात भी कहाँ सुन रहे हैं! वे special status की माँग कर रहे थे। मैं उस समय बिहार विधान सभा में काम करता था, तो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री, आदरणीय आडवाणी जी जब राज्य का बँटवारा कर रहे थे, पता नहीं अभी वे किस हालत में हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाएँगे। हम लोग बिहार को 1,79,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे।...(**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : अखिलेश जी, आपको extra time भी मिल गया है, इसलिए अब आप समाप्त कीजिए।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि उस पैकेज का क्या हुआ? पिछली विधान सभा चुनाव के समय में जब आदरणीय प्रधान मंत्री जी वहाँ गए, तो उन्होंने कहा कि हम बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे। उस पैकेज का क्या हुआ?...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): But five minutes will be reduced because we have to complete it today.

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : बेचारे नीतीश जी एक छोटी-सी घोषणा की माँग करते रह गए कि पटना विश्वविद्यालय को सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। उस घोषणा का क्या हुआ? कैबिनेट सेक्रेटरी गौबा साहब इसी यूनिवर्सिटी के हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 5-6 सेक्रेटरीज़ इस विश्वविद्यालय के हैं और न जाने कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, लेकिन उस पर भी आपका ध्यान नहीं जाता है। मुझे लगता है कि जब आप जवाब देंगी, तब आप प्रधान मंत्री जी से पूछ कर कम से कम वह घोषणा करवा दीजिएगा।

रोहतास इंडस्ट्री था, दोला बहन ने कल जूट इंडस्ट्री की बात की, पूर्णिया, कटिहार का वह पूरा इलाका इससे संबंधित है। सारी शुगर मिल्स बंद हैं। काँग्रेस की हुकूमत में सारे पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट आए, चाहे वह बोकारो का कारखाना हो, हटिया का कारखाना हो, बरौनी का कारखाना हो, बाढ़ और मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर प्लांट आया, लेकिन इस हुकूमत में बिहार में क्या आया? आप बिहार के साथ ऐसे सौतेलेपन का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बिहार से लोक सभा की 40 सीट्स हैं। जब आपकी सरकार बनी थी, तब लोगों ने आपको 40 में 39 सीट्स पर जिता कर भेज दिया और एक सीट पर काँग्रेस पार्टी जीती।

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : कृपया अब आप समाप्त कीजिए। मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूँ।

श्री अखिलेश प्रसाद सिंह : सर, मैं अपनी आशाओं को व्यक्त करने का मौका पाकर और आधी बात कहने का अवसर पाकर आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (**श्री भुबनेश्वर कालिता**) : आपको आगे भी मौका मिलेगा। Now, Dr. Sudhanshu Trivedi. You have 20 minutes from your Party.

डा. सुधांशु त्रिवेदी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं वित्त मंत्री महोदया के द्वारा प्रस्तुत इस बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बजट कोई सामान्य बजट नहीं है, क्योंकि यह 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' वर्ष, जिसके आगे के समय के लिए प्रधान मंत्री जी ने 'अमृत काल' शब्द का प्रयोग किया है, यह ऐसे बहुत से अमृत तत्वों को सन्निहित किए हुए, समाज के लिए अनेक कल्याणकारी विषयों को लेते हुए प्रस्तुत किया गया है। देखिए, जब अर्थ की बात आती है, तब यह कह जाता है कि अर्थ का कितना महत्व है।

[**उपसभाध्यक्ष** (**श्रीमती वंदना चव्हाण**) *पीठासीन हुईं*]

महोदया, हमारे यहाँ संस्कृत के सुभाषित में कहा गया है - "अर्थ सर्वजगन्नमूलः अनर्थो अर्थ विपर्यः", इसका अर्थ होता है कि संपूर्ण जगत के क्रियाकलापों का मूल 'अर्थ' है, 'finance' है, इसीलिए अनर्थ, जिसका उपयोग सब कुछ नष्ट होने के अर्थ में होता है, वह इसके विपरीत शब्द के रूप में प्रयोग होता है। मैं इस बजट के अर्थ को समझने के लिए आंकड़ों पर बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी विद्वान लोग बैठे हुए हैं और उन्हें आंकड़ों के बारे में पहले से बहुत जानकारी है, परंतु इस अभिलेख का निहितार्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, यह समझने की आवश्यकता है।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, वित्त मंत्री महोदया ने प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर जो विषय रखा है, वह तीन मूल भावनाओं से प्रेरित है। पहला, कल्याणकारी योजना और सर्वस्पर्शी विकास। दूसरा अपने आप ही इससे रिलेटेड प्वाइंट आता है कि यदि हमें सर्वस्पर्शी विकास और कल्याणकारी योजनाएं आगे ले जानी हैं, तो वे किससे प्रेरित होनी चाहिए? वे भविष्य की आवश्यकताओं से प्रेरित होनी चाहिए, जैसे पर्यावरण संतुलन, ग्रीन एनर्जी और हाई टेक्नोलॉजी। आपके मन में अगला प्रश्न उठेगा कि यदि यह सब संचालित होना चाहिए, तो इसके लिए धन और संसाधन की व्यवस्था कहाँ से होनी चाहिए? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें पब्लिक के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सक्रिय और सकारात्मक सहयोग के साथ संसाधन जुटाने की व्यवस्था की गई है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि This is welfare-oriented all-inclusive development motivated by the futuristic and high technologies like ecological balance and green energy with an active and vibrant participation of the private sector also. अब आप कहेंगे कि आपने यह सब कुछ कह तो दिया, परंतु क्या यह संभव है, हम इसे कैसे करेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने यह करके दिखाया है। अभी बजट में विकास की दर 9.2 प्रतिशत रखी गई है। कल सुशील कुमार मोदी जी ने भी इस बात का उल्लेख किया था कि IMF ने अभी 25 मार्च को अपनी जो रिपोर्ट दी है, उसके Revised Estimates में भी भारत का projected growth rate 9 प्रतिशत रखा है, यानी जो हमने स्थापित किया है, उसके एकदम अनुरूप है या यथार्थ पर है। दूसरा, जो fiscal deficit, वित्तीय घाटा था, जिसका लक्ष्य 6.8

प्रतिशत रखा गया था, वह 6.9 प्रतिशत है, यानी उसे भी हमने लगभग पूरी तरह से attain किया है। जबकि यह fact है कि हमने इसमें massive capital expenditure भी बढ़ाया है और इस वर्ष 34 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है, मेरे विचार से इसके बावजूद वित्तीय घाटे पर नियंत्रण के लिए वित्त मंत्री महोदया साधुवाद की पात्र हैं।

महोदया, यहाँ एक और बात भी है कि tax collection का जो टारगेट था, वह 22.17 लाख करोड़ रुपए था, जिसे बाद में revise करके 25.16 लाख करोड़ रुपए किया गया और जो actualize हुआ, that is Rs.26.13 lakh crore. यानी, हमने जो तय किया, उसके आगे तय किया, फिर हमने उससे कहीं बेहतर realize किया। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी योजनाएं, अनुमान और वित्तीय प्रबंधन, सब ठोस तथ्यों पर आधारित हैं।

इसमें एक फैक्टर और भी है। अभी State Bank of India का एक सर्वे आया है, जिसके अनुसार 2017-18 में भारत की informal economy, जो लगभग 52 प्रतिशत के आस-पास थी, वह अब 15 से 20 प्रतिशत के आस-पास हो गई है, जो कि अधिकांश विकसित देशों के parameters के अनुरूप है। इसका अर्थ यह हुआ कि विगत दो-तीन बजटों के द्वारा जो निरंतर प्रयास किए गए हैं, वे अपना प्रभाव दिखा रहे हैं और अर्थव्यवस्था एक नए स्वरूप और नई शक्ति के साथ युक्त हो रही है, परंतु मैं यहाँ भी कहना चाहूँगा कि यह सब हमने किस समय अचीव किया है। जब सरकार के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप यह बताइए, इस समय जब विश्व मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था, 200 देश Covid से affected थे... In the documented history of world, nowhere you can find any reference that 200 countries are facing the same problem. इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर सन् 2020 का वह वर्ष जब इंग्लैंड का ग्रोथ रेट minus 9.3, अमेरिका का minus 5.6, इटली, जर्मनी, फ्रांस का minus 10 था, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस परिस्थिति के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं! मेरे विचार से इतने प्रबुद्ध लोग, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, विदेश गमनागमन में संलग्न जो अनेक नेता हैं, कम से कम उनको तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए! विश्व के इतिहास में आप कोई example बताइए। जब all G-7 countries are having negative growth rate, उस दौर में हम इकलौते ऐसे देश थे, जब देश के अंदर भी सब मोदी जी पर आक्रमण करने के लिए खड़े थे, तब उन्होंने बहुत ही दृढ़ता का परिचय दिया, चाहे कोई साथ खड़ा था या नहीं खड़ा था। मुझे महादेवी जी की प्रसिद्ध कविता, 'पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला' की एक पंक्ति याद आती है:

"अन्य होंगे चरण हारे,
और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे;
चिरव्रती निर्माण-उन्मद
यह अमरता नापते पग;
बाँध देंगे अंक-संसृति से तिमिर में स्वर्ण वेला!
पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला।"

बजट पर जब आगे विचार किया गया, तो एक और तथ्य सामने आया, जिसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं था। लोग कहते थे कि साहब, expenditure के लिए further लोगों को पैसा

क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है? सरकार द्वारा सब प्रकार की व्यवस्थाएँ की गईं, परन्तु एक fact भी है। पिछले एक वर्ष में इंडिया की जो household savings है, वह 7 लाख करोड़ रुपये बढ़ी और household debt 18,000 करोड़। यहाँ तक कि जो 45,000 जन-धन अकाउंट्स हैं, जिनमें सबसे गरीब, वंचित और निर्धन लोगों के अकाउंट्स हैं, उनकी सेविंग्स में 39,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। यह इस बात का प्रमाण है कि pandemic के इस दौर में एक मनोविज्ञान है कि जनता अभी बचत की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद कोविड काल पूर्णतः समाप्त हो जाए, तब वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में आएँगे। वित्त मंत्री जी ने पूरी संवेदना के साथ उस विषय का ध्यान रखा है कि उन्होंने न कोई टैक्स लगाया है, न इंटरेस्ट रेट्स में कोई कमी की है, यानी जनमानस की उस भावना का उन्होंने यहाँ पर पूरा सम्मान किया है।

सर, यह दौर दुनिया का ऐसा दौर था, जिसमें से हम सिर्फ बचकर नहीं निकले, हमने सिर्फ survive नहीं किया, बल्कि हमने एक नए सृजन का आधार भी बनाने का प्रयास किया। यह हादसा था, हादसा बड़ा खौफनाक था, पर ऐसा नहीं है कि हमने हिम्मत हारी। मैं कहना चाहूँगा कि हमने इस विचार को ध्यान में रखा किः

'हादसों का दौर है, तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें
और जलजलों के खौफ से घर बनाना छोड़ दें?'

इसलिए हमने एक नई व्यवस्था का निर्माण शुरू किया और उस व्यवस्था के निर्माण का आधार हमने क्या बनाया? वह आधार, जिसकी प्रधान मंत्री जी ने नींव रखी है, जिसका वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में प्रावधान किया है, वह है - 'गति शक्ति।' 'गति शक्ति' में चाहे रेल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, logistic support हो, mass transportation हो, ये seven engines of growth हमारे भविष्य के एक बड़े भव्य भवन का आधार बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। **...(व्यवधान)...** फिर, 25,000 करोड़ रुपये National Highway के लिए हों या रेलवे में 'एक प्रोडक्ट, एक स्टेशन' बनाने की बात हो, यानी भारत के अंदर जो एक सृजनात्मक क्षमता है, उसका अर्थ-जगत में कैसा प्रयोग किया जाए, उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। मैं बहुत विस्तार में न जाते हुए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चाहे MSME में ECLGS को वर्ष 2023 तक बढ़ाना हो, 5 लाख करोड़ का कवर देना हो और यह तय करना हो कि प्रधान मंत्री जी ने जो अभी बोला था कि 200 करोड़ रुपये से अधिक के टेंडर्स ही ग्लोबल होंगे और उसके नीचे इसका सर्वाधिक लाभ भारतीय कंपनियों और MSME को ही प्राप्त होने की संभावना है, चाहे Make in India में 60 लाख जॉब्स क्रिएट होने हों, 400 'वन्दे भारत' ट्रेनें चलनी हों, क्या इनमें से कोई भी job creation के बगैर होगा? चिदम्बरम साहब बोल रहे थे कि उन्हें जॉब का उल्लेख दिखाई नहीं पड़ता है, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा कि वे हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना विकास होगा, तो क्या उसमें जॉब्स क्रिएट होती दिखाई नहीं पड़ेंगी? यह सहज स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है।

महोदया, अगला पक्ष सुरक्षा का आता है। हमारी सरकार ने सुरक्षा के मामले में सबसे बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन किया है। मैं कभी सोचता था कि हमारा देश चंद्रयान बना सकता है, तो मिसाइल क्यों नहीं और अगर मिसाइल बना सकता है तो assault rifle क्यों नहीं? ऐसा नहीं है कि

हमारे अंदर क्षमता नहीं थी। हमने डिफेंस प्रोडक्शन शुरू किया था। आपने देखा कि इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि जितना भी defence production होगा, उसमें 68 परसेंट capital procurement डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगा, यानी हम डिफेंस के क्षेत्र में gradually self-reliant, यानी आत्मनिर्भर होते चले जाएंगे। महोदया, दूसरा काम यह किया है कि DRDO ने अभी तक जितनी भी Research and Development (R&D) की थी, उसको अब इंडस्ट्री और ऐकेडेमिक्स दोनों के लिए open कर दिया है, यानी जो कुछ हमने नई टेक्नोलॉजी अर्जित की है, अब उसको व्यापक रूप से, सहज नैसर्गिक रूप से विकसित होने का आधार भी मिले, यह सुनिश्चित किया है, जबकि डिफेंस सबसे बड़ी मद है, यह 3.85 लाख करोड़ है। अगर इसमें 1.2 लाख करोड़, जो पेंशन में जाता है, उसको include कर लें, तो 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की मद है।

महोदया, यदि किसान को देखें तो चाहे एमएसपी में 2.37 लाख करोड़ रुपये देने हों, पांच बड़े river-linking projects, जिनमें Ken-Betwa project के लिए 1,400 करोड़ रुपये का प्रावधान हो - इसके साथ-साथ कृषि स्टार्टअप के लिए अब NABARD फंडिंग करेगा। अब फल, सब्ज़ी उगाने वाले किसानों को पैकेज मिलेगा। नई टेक्नोलॉजी के द्वारा किसानों को किस प्रकार से आगे किया जा सकता है - पहले आपने देखा कि प्रधान मंत्री जी ने जनधन अकाउन्ट खुलवाकर direct benefit transfer और GeM के द्वारा किसानों को सशक्त किया - अब ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा, चाहे कीटनाशकों का स्प्रे हो, सीड्स का स्प्रे हो अथवा मैपिंग हो, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या होती है कि मैपिंग उतनी appropriate नहीं होती, जिस कारण से विवाद होता है। महोदया, ड्रोन से बड़ी दूर की दृष्टि नज़र आती है, तो मुझे कभी-कभी नाम की समानता से याद आता है कि आचार्य द्रोण भी थे, जिनको बड़ी दूर की दृष्टि नज़र आती थी, मगर क्या करें, वे युवराज के हठ के आगे विवश थे, ऐसे ही कुछेक अनुभवी दूर-दृष्टि वाले व्यक्ति उधर भी हैं, मगर इतिहास ऐसा है कि आज भी वे युवराज के हठ के आगे विवश हैं।

महोदया, गरीबों को 80 लाख मकान देने हों, 3.6 करोड़ लोगों को नल से जल देना हो - महोदया, जो लोग गरीबी की बातें कहते हैं, वे बड़े मज़े की बात कहते है, मगर भारत की राजनीति में बड़ा विचित्र अर्थशास्त्र है, जो गरीब और वंचित की बात कहते हैं, उन्हीं के नेता देखते-देखते सबसे पहले सैकड़ों करोड़ की सम्पत्ति के मालिक हो जाते हैं। महोदया, गरीब-गुरबा की राजनीति करने वाला परिवार आज सबसे अमीर परिवार है, वंचितों और शोषितों की एक नेता आज सैकड़ों करोड़ की नेता है, मज़दूर और किसान के नेता आज सैकड़ों करोड़ के नेता हैं। उनका अर्थशास्त्र अलग है और अर्थशास्त्र को देखने का नज़रिया भी अलग है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी न करते हुए आगे कहता हूं कि हम भविष्य में और आगे बढ़ें।

महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज 10 फरवरी है, शायद बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन मैं बता दूं कि 26 साल पहले 10 फरवरी, 1996 को उस समय के शतरंज के वर्ल्ड चैम्पियन Garry Kasparov ने IBM के कम्प्यूटर Deep Blue के साथ शतरंज की पहली बाज़ी खेली थी, यह शुरुआत थी जो digital technology का पहला चरण था, आज 26 साल में वह कहां पहुंचा - शायद उस समय लोगों ने कल्पना नहीं की होगी, इसीलिए मैं कहता हूं कि 'अमृत काल' में वित्त मंत्री महोदया ने और प्रधान मंत्री जी ने जो दृष्टि दिखाई है कि अगले 25 साल में हम कहां पहुंचेंगे, इसके लिए digital technology को strong करना ज़रूरी था, इसीलिए digital को, data को infrastructure का दर्जा दिया गया है। महोदया, अर्बन और रूरल में जो

digital divide है, उसको भी समाप्त करने का प्रयास किया गया है। RBI ने digital currency शुरू की है, यानी हमने आगे की दृष्टि देख ली है कि आने वाले समय में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, भविष्य में नई टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से यूज़ होगा, चाहे Sovereign Green Bonds हों। पिछली बार, आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले बजट में hydrogen energy का उल्लेख था, ताकि वह आगे बढ़ सके। इस बार वर्ष 2030 तक 280 Giga watt solar energy के उत्पादन का लक्ष्य भी सुनिश्चित किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में जवान के भविष्य की व्यवस्था है, किसान के भविष्य की व्यवस्था है और विज्ञान के भविष्य की भी व्यवस्था वित्त मंत्री महोदया ने सुनिश्चित की है।

महोदया, एक विषय यह है कि कहा जाता है कि कोरोना काल में negative growth rate हो गया। मगर मैं आपके माध्यम से सदन के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि वर्ष 2022 negative growth rate का भी स्वर्ण जयन्ती वर्ष है। वर्ष 1972 में भारत का growth rate minus 0.55 per cent था, लेकिन जब यह कहा जाता है कि पहली बार negative growth rate हो गया तो मैं सुलभ संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि चार बार इस देश का negative growth rate रह चुका है। हम तो उस दौर में हैं, जब पूरी दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा दौर था, उसमें negative growth rate था। परन्तु अगली बात आती है कि आज 5.59 प्रतिशत का इन्फ्लेशन है। भारत सरकार के असेसमेंट को लेकर अगर इनके मन में कोई संदेह रहता है तो ईवन रायटर्स ने भी जो अपना असेसमेंट किया है, उसमें 5.8 परसेंट कहा है, पर मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब यह कहा जाता है कि यह भारत के इतिहास की सबसे बड़ी महंगाई है तो हम भूल जाते हैं कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन इस देश में कितनी बार रहा है। 2010, 2009, 1997, 1995, 1994, 1992, 1991, 1983, 1981, 1980. 1974 में 28 प्रतिशत और 1973 में 17 प्रतिशत - 28 प्रतिशत और 17 प्रतिशत का रेट ऑफ इन्फ्लेशन इस देश में रहा है। देश में 2019 का और 2004 का ही चुनाव ऐसा था, जब महंगाई मुद्दा नहीं बनी, वरना हमेशा महंगाई मुद्दा बनती थी और उस दौर में महंगाई इतनी रही है कि जनमानस के लोकगीत और रंगमंच में महंगाई उल्लिखित हो जाती थी। हम सब को याद होगा, 'सखी सैंया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाये जात है', यह गाना किसके जमाने में बना था? बचपन में हम लोगों ने, हमारे होश संभालने से पहले का अगर आप लोगों को याद होगा तो 'पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, राशन वाली लाइन की लम्बाई मार गई और बाकी जो बचा था, वह महंगाई मार गई।' यह गाना बचपन में हमने खूब सुना है, इसलिए जब आप कहते हैं कि साहब, महंगाई अभूतपूर्व है और पहली बार है तो यह अपने आपमें बहुत अनरियलिस्टिक लगता है।

अब एक फैक्ट मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। आजकल चर्चा है कि पैट्रोल की कीमत बहुत बढ़ रही है, यह 23 नवम्बर, 2021 की व्हाइट हाउस का रिलीज़ है। व्हाइट हाउस प्रेस रिलीज़ कहता है, 'President Biden announces release from the strategic petroleum reserve as part of ongoing efforts to lower prices and address lack of supply around the world.' क्या हमारे प्रबुद्ध विपक्षियों में से कोई बता सकता है कि अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कब खोला था? यह बताइये। यह व्हाइट हाउस कह रहा है कि दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, तो क्या इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार हैं? जिस प्रकार की वैश्विक परिस्थितियां और यथार्थ था, उसे समझने की जरूरत है। दर्जन बार, 12 बार तक, दहाई अंक तक महंगाई बढ़

चुकी है, दर्जन बार इनकी महंगाई दहाई अंक को पार करे, तब अगर वे महंगाई की दुहाई दें तो उसमें सच्चाई नज़र नहीं आती है।

अब मैं एक बिन्दु और भी कहना चाहूंगा, जैसा आपने देखा, कल हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बड़ी ही शिद्दत के साथ मार्क्स को क्वोट कर रहे थे। देखिये, मार्क्स यानी कम्युनिज़्म और कैपिटलिज़्म, यह माना जाता है कि दोनों एक-दूसरे के विरोधी हैं। हमारे विपक्षी दल लम्बे समय सत्ता में रहे, उन्होंने एक समय एक विचारधारा को माना, दूसरे समय दूसरी विचारधारा को माना, परन्तु दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। सब कहते हैं कि धन संसाधन हैं, जितना हो सके प्रकृति का भयंकर दुरुपयोग करो, जितना अधिक से अधिक पैसा होगा, फिर वही सुख का कारण बनेगा। धन एक संसाधन है, मानव भी एक संसाधन है, प्रकृति भी एक संसाधन है, केवल ओनरशिप का झगड़ा है। एक कहता है कि सरकार के पास रहना चाहिए, एक कहता है कि प्राइवेट के पास रहना चाहिए, लेकिन दोनों पूर्णतः भौतिकवादी हैं। हम जब मानते हैं तो हम धन को संसाधन नहीं मानते, हम उसे लक्ष्मी माता मानते हैं, इसलिए उसमें चेतना देखते हैं और स्नेह देखते हैं, इसलिए वह सब को समान रूप से अपना लाभ पहुंचाने का प्रयास करती है। यह एक अंतर है, हमारी सोच और उनकी सोच में - जो मार्क्स की सोच है और जो भारतीय सोच है। इसीलिए धन जब सिर्फ संसाधन होता है तो उसका आसन किसी भी कुशासन में, किसी भी दुशासन की तिजोरी में हो सकता है। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, you will have to start winding up.

DR. SUDHANSHU TRIVEDI: I will.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You have one minute left.

डा. सुधांशु त्रिवेदी : परन्तु जब वह कल्याणकारी जीवन चेतना द्वारा समाज में कल्याण करने के लिए लक्ष्मी मां के रूप में आता है, तो उसका आसन सिर्फ कमल ही होता है। इसीलिए आपने देखा कि जब से ये आये हैं, तब से निरन्तर कल्याण की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।

अंत में, मैं ज्यादा समय न लेते हुए कहना चाहूंगा, कल कपिल सिब्बल जी जब समाप्त कर रहे थे, उन्होंने गाहे-बगाहे औरंगजेब का भी उल्लेख कर दिया और जज़िया में भी अर्थशास्त्र देखने लगे। अब क्या करें, इनकी फितरत ही ऐसी है कि जब कांग्रेस के लोग बोलते हैं तो कहीं न कहीं वे उल्लेख कर ही देते हैं। हम भी सिर्फ यह कहना चाहेंगे, हम जब अर्थशास्त्र का संदेश लेते हैं तो कहां से लेते हैं, भगवान राम के उस सिद्धांत से, जो कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन कैसे होना चाहिए, जैसे सूरज करता है, वह जहां सरोवर है, उससे ज्यादा पानी लेता है, नदी से ज्यादा लेता है, मिट्टी थोड़ी है, उससे कम लेता है, परन्तु जब बरसाता है तो सब पर समान रूप से बरसाता है, जिसे तुलसीदास जी ने लिखा है, 'बरसत हरषत लोग सब, करषत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग ते, भूप भानु सो होइ।' इससे आपको यह भी समझना चाहिए कि हम कहां से, उस भक्ति में से कितनी शक्ति लेते हैं और कहां से गति लेते हैं।

महोदया, मैं बस दो-तीन सेंटेंस में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। एक ज़माने में लोग कहते थे, हमारे ऊपर आरोप लगता था कि "रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे", उसका अर्थशास्त्र क्या था? वर्ष 1947 में जब यह देश गुलामी के चंगुल से आज़ाद हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था मुक्त हुई और 1949 में रामलला प्रकट हुए। वर्ष 1990-92 के दौर में जब पुरानी अर्थव्यवस्था का ढांचा टूटा और एक नई अर्थव्यवस्था उभरी, तो वहां से राम जन्मभूमि का एक बड़ा आंदोलन उभरा। आप एक बात देखिए कि उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व एक बिलियन से कम था। जब हमारी गठबंधन में अटल जी की सरकार आई, तो वह 100 बिलियन पहुंचा और जब स्पष्ट बहुमत से हमारी सरकार आई,...(**व्यवधान**)... तो वह 500 बिलियन पहुंच गया।

उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं। अब वह 600 बिलियन पहुंचा गया है, इसलिए यह बजट बताता है कि जो हमसे कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, तो आश्वस्त रहिए, हम तारीख में वह मुकाम दिखाएंगे कि भारत माता के वैभव का भव्य मंदिर और इस राष्ट्र के गौरव का श्रीराम मंदिर, दोनों हम ही बनाएंगे और मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्र अपनी नाकाम हसरतों का मरसिया पढ़ते रह जाएंगे।

DR. PRASHANTA NANDA (Odisha): Madam, the highlights of this Budget 2022-23 are research and development infrastructure, capital expenditure, digital health platform and digital currency, which definitely would go a long way for the economy of the country. But, this Budget has no answer for the current price rise for which the middle-class, poor and farmers are facing a lot of problems.

Rise in prices of petrol, diesel and cooking gas and other household commodities has made the housewife's life helpless in tackling their family budget. This Budget must have disappointed them. Reduction in MNREGA in a pandemic situation is not going to help the poor people. Serious issues like the off-taking by FCI leading to dislocation in paddy procurement and further reduction in food subsidy under NFSA will put the farmers in a serious trouble. This may be considered. The increasing level of cess and surcharge is shrinking the mandated transfer of shared tax due to the States. More than 20 per cent of the Union taxes are proposed to be collected through the levy of cess and surcharge, which is against the spirit of cooperative federalism.

Madam, I would like to draw the kind attention of the hon. Minister to the steep increase in the State's share of the Centrally-sponsored schemes. Delinking of eight Centrally-sponsored schemes from the Central support, abolition of normal Central assistance and steep increase in the States' share of Centrally-sponsored schemes have imposed severe financial burden on the State. For example, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana was earlier fully funded by the Government of India. But, now the share of the Government of India has come down to 60 per cent, requiring 40 per cent

funding by the State Government as a matching share. Similarly, the sharing pattern of the National Health Mission on Pradhan Mantri Awas Yojana has been revised with States like Odisha having to contribute 40 per cent share instead of 25 per cent share provided earlier. Such a change in the sharing pattern of cess have cast a huge financial burden on the States, leading to much less resources for the State's schemes, appropriate to our needs.

Madam, due to Covid pandemic, the Government of India have projected a shortfall of State GST and IGST share for the States. As per the discussion in the GST Council Meeting, it was decided that the Ministry of Finance, Government of India, will arrange back-to-back loan to the States in lieu of GST compensation shortfall on account of implementation of GST. The balance compensation due to Covid-19 will be paid from the compensation fund after the transition period, that is, 30.6.2022. The principle of back-to-back loan and interest accrued thereon will be paid from the compensation fund collected after the transition period. The State Governments are not required to pay towards the back-to-back loan and the interest accrued thereon. The Government of Odisha prefer the above-mentioned.

Madam, the economic divide emanating from an asymmetric growth and backwardness of regions, dominated by tribals and vulnerable groups, gives rise to the regional imbalance, which calls for focussed attention of the Government for achieving inclusive growth. The Left-Wing extremism is one of the biggest internal security threats which poses a national challenge.

Discontinuation of Central assistance for area development programmes like Special Plan for KBK, Backward Region Grant Fund and Integrated Action Plan for LWE-affected districts have affected the developmental programmes for some of the vulnerable and backward regions of Odisha. The Government of India is requested to provide a special package to the State for continuation of this programme from the Budget provisions available from NITI Aayog.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Kindly wind up.

DR. PRASHANTA NANDA: Lastly, I would appreciate if the hon. Minister responds to the concerns of my State as I have narrated. Thank you, Madam.

SHRI K. J. ALPHONS (Rajasthan): Madam Vice-Chairman, I strongly support the Budget. First of all, I would like to speak a few sentences on the macro-economic fundamentals of this nation. Last year, we spent Rs. 2.64 crores more than what was budgeted. Generally, the main allegation of the Opposition is, 'you are budgeting, you are preparing a document, but the money is not being spent.' We have spent

Rs. 2.64 crores, which is more than what was budgeted. Look at our fundamentals. Growth rate of 9.2 per cent makes India the fastest growing large economy in the world. Not only that... ...*(Interruptions)*... Yes, Madam, it is the fastest growing large economy in the world at 9.2 per cent. You can dispute my figures if you would like to and according to IMF projections, Madam, India is going to be fastest growing large economy over the next three years. These are all projections, but this is a fact. It is 9.2 per cent. Our fiscal deficit of 6.9 per cent is one of the lowest globally because pandemic is something which the world never faced; as my friend Sudhanshuji mentioned it is the biggest tragedy in the history of the world. Look at the way India faced it! The answer was very simple. We provide whatever is necessary. The Government went to any extent to provide purchasing power at the hands of the people, to create medical facilities, to vaccinate 170 crore people in this country. Madam, still the fiscal deficit is only 6.9 per cent and is projected to come down to 6.4 per cent this year. I have a slight difference of opinion on this because I believe, in the times of pandemic, when your consumption needs to increase dramatically, you don't need to go for fiscal austerity. You don't really need to confine your fiscal deficit to 6.4 per cent; even if it goes up a little bit, it does not really matter. Our foreign exchange reserves of 634 billion dollars is the highest in the world. Our FDI of 89 billion dollars is the highest in the world. Our tax realisation was buoyant, direct taxes and indirect taxes, our exports are historical. Madam, this places Indian economy, the macro fundamentals of Indian economy, on an extremely sound footing in these difficult times. I am not saying we are out of the woods yet. We still need to do more. That is precisely why the Modi *Sarkaar* needs to be here for many more years to come because we don't claim to have done everything. We are in the process of doing it. There is a big debate going on where names were mentioned, that the rich have grown richer and therefore, find a solution. This has been the argument of India's socialism for the past 75 years. What has been the solution? Names were mentioned that the wealth of 'X' and 'Y', two people, have gone up by 'X' per cent. Madam, the wealth of one man, Elon Musk, you know how much has it gone up over the past one year? Elon Musk's wealth has gone up 1016 per cent. Are you aware of this? The wealth of the founder of Google, Larry Page, has gone up 126 per cent. The wealth of Bezos has gone up 67 per cent. The lowest among all the top ten is Bill Gates. His wealth has gone up 30 per cent.

Madam, global inequality is a fact, whether you accept it or not. Three billion people in the world live below five dollars a day. So, the global inequalities are a fact. What is the solution of the Opposition? They have not used the words 'kill the rich'. They have not used these words. But, what did they try to do for seventy years?

What was the income tax in India in 1980s? It was 97.5 per cent, which killed them. You killed them till a sensible man Narasamiha Rao came along with Manmohan Singh and said that that was not practical; we need to liberate the animal spirits of the private sector; we need investment. They had the courage to do it. I place on record my appreciation for them. Shri Narasimha Rao and Dr. Manmohan Singh did it. But, of course, slice-by-slice, the country was sold off. I have written a very objective book on Modi Government. This is not an adulatory book. There are a million facts in this book. I vouch for the figures. Anybody can challenge me. In the epilogue, which is actually the introduction to the book, I have said, "Every Prime Minister who has been in power has done something good for India. Nehru loved the country passionately. He laid the foundations of science and management education in India. Indira Gandhi had the courage to stand up against to global bullies. Rajiv Gandhi could charm the world with his youthfulness and spirit of enterprises. Many of them had their share of failures and some colossal." Madam, colossal! My father was a soldier, he fought the Second World War at the battle of Kohima. He was lucky that he did not die. As the son of a soldier, let me tell you that I am extremely proud of the man 'Narendra Modi' who is the Prime Minister of India because he has the courage to stand up for India. When 38,000 sq. kilometers of Indian territory was swallowed by China in 1962, somebody raised that issue in the Parliament and asked, "Nehru*ji,* what is happening? What did you do?" He said, "Sorry, not a blade of grass grows there. What is the point? We haven't lost anything" Then, somebody pointed out, "Nehru*ji,* there is not one hair on your head. Why do you need your head? Why don't you chop it off?" Parliament debated it. As the son of a soldier, I feel proud when we take on our enemies in Balakot, when we take them on in Pangong Tso, when we take them on in Galwan Valley, when our defence forces are strengthened. A former Defence Minister is on record, "We will not create any infrastructure on the borders because the enemy can march in." This is on record. Do you want to see the video of the former Defence Minister where he is saying that we don't want to build the infrastructure? We are building 10133 kilometers of roads on the borders, built advanced landing fields, we are acquiring latest aircrafts. Today, 68 per cent of arms are being produced indigenously. But, you will say, "Why are you giving it to private sector?" Learn from the global community. The best equipments in the whole world are produced by the private sector, not by the government Defence Ordinance Factories. Did you have boots, bulletproof vests for our soldiers when you were in power? Did you have that? We got them. We empowered them. We gave them money. As the son of a former soldier, I am proud of my Prime Minister. And, here was a prominent Member of Parliament, speaking the other day, saying, "India is

bowing its head in front of the international community". Madam Vice-Chairman, Hon'ble Kharge*ji* was saying the Christian community has been persecuted. I have never seen such happiness on the face of the Pope when he embraced India's Prime Minister, Narendra Modi*ji*. I have never seen such happiness. American President went to see him. He did not embrace him. When the President tried to go closer, the Pope moved back. The biggest moral leader in the world, the Pope, when he embraced Modi*ji*, that was the biggest sign of happiness. And, you people spread the canard that the Christians are being persecuted in India. A party, which burnt alive 5,500 people in Delhi said, "When a banyan tree falls, it is bound to happen". I was in Kerala those days. When I came back to Delhi as Commissioner, DDA, I paid my little bit back. The first building I demolished, belonged to the leader of that gang, H.K.L. Bhagat, let me name the man. And, what was the size of the building that I demolished? It was two lakh square feet. Just two lakh square feet! I paid back. I paid back. This was my little way of paying back to the country. You can accuse me of being a mouthpiece of the capitalists. The people who have created jobs in this country, let me name those people, because you have named them, be it Reliance, be it Ambani, be it Adani, be it anybody, they must be worshipped. Yes, because they provide jobs. Manoj Jha*ji*, let me tell you, your leader, ...*(Interruptions)*.. your party, ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please address the Chair.

SHRI K.J. ALPHONS: Cattlefeed meant for the cattle....*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Mr. Alphons, please address the Chair.

SHRI K.J. ALPHONS: What did you do? How many jobs have you created. ..*(Interruptions)*.. Let me ask?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, please.

SHI K.J. ALPHONS: How many jobs have you created individually? We Members of Parliament don't create jobs, Manoj Jha*ji*.....*(Interruptions)*.. The people who invest money, Ambani, Adani, every industrialist who creates money in this country creates jobs. ..*(Interruptions)*.. They have created jobs. ...*(Interruptions)*.. They need to be respected. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, please address the Chair. Don't talk amongst yourselves.

SHRI K.J. ALPHONS: Madam, they might think I am being the voice of the capitalists. Yes, I was with Mr. Mukesh Ambani in Time Magazine's list of hundred young global leaders. I have not had a coffee with Mukesh Ambani ever, nor with Adani. I have not taken a meal from anybody. You come to my house and see. My house is a commune, true commune, Jhaji. You come and see. There are 43 people living in my house. One small little baby was born yesterday. We had a huge reception. ...*(Interruptions)*.. 43 people living in my house as a commune. Come and see. ...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, please address the Chair. ...*(Interruptions)*..

SHRI K.J. ALPHONS: Madam, every country honours the people who create jobs. ..*(Interruptions)*.. This Parliament, this House, the people sitting out there, you shame them. They must be honoured, they must be recognised. If I am using a word, an exaggerated word, pardon me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, your time is over. Please wind up. You have only a few seconds left.

SHRI K.J. ALPHONS: Madam, I have hardly begun. Let me make a couple of points. All these things we have to...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Your time is over. You had 12 minutes. Only one minute is left.

SHRI K.J. ALPHONS: Our Prime Minister, over the past seven years, spent most of the money on creating infrastructure for the poor. Madam, when we built 11 crore toilets, did the angles from Heaven come and build these toilets?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You will have to wind up.

SHRI K.J. ALPHONS: We built 11 crore toilets. ..*(Interruptions)*.. You multiply 11 by at least 10, that is 110 crore mandays. ..*(Interruptions)*.. When we built two crore houses, you multiply that by 500 man days per house, that makes it 1,100 crore

mandays. We built hospitals, we built roads. About 850 crore mandays were created by building roads. Is it not employment?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, your time is over. Please wind up. I will have to call the next speker. Please conclude.

SHRI K.J. ALPHONS: Is it not employment? My last point, please permit me. I am concluding. My last point is, should we sell our public sector? Madam, it is our money which is invested. Air India ate up Rs.65,000 crores. When should we privatise? Privatise them when their value is highest, not when they are finished.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Thank you, Mr. Alphons.

SHRI K.J. ALPHONS: As for LIC, we are not privatising it. We are only giving four to five per cent of the equity to the public which created that wealth...*(Interruptions)*..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): You will have to wind up.

SHRI K.J. ALPHONS: This is the time to sell it. When it has a value, we sell it because this is value for the people. I support the Budget.

श्री महेश पोद्दार (झारखंड) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदया, हमरे सामने जे लोग बैठल हैं, वे लोग बार-बार पूछते हैं कि बजटवा में का बा? वे बार-बार पूछते हैं कि इस बजट में का है, का बा? हम बोलेंगे - ए भैया, इ बजटवा में बहुत-कुछ बा, अब आप सुनी। 75 से 100 के रस्ता बा, रोज़गार के जुगाड़ बा, गरीबन की खातिर घर बा, नल से जल बा।.. (**व्यवधान**)..7.5 करोड़ के पूंजी खर्चा बा, एक लाख के खर्चा राज्य सरकार के बा। नइका-नइका ट्रेन बा, बड़का-बड़का सड़क बा। गाँवन में सड़क बा, गंगा से कैमिकल के मुक्ति बा। भारत में देसी जहाज बा, देस में बनल तोप और बंदूक बा। कोरोना से बचल के उपाय बा, भारत के महाशक्ति बनाए के उपाय बा। क्रिप्टो पे टैक्स बा, विदेशी छात्रों के ऊपर भी टैक्स बा। छोट फैक्टरी के खातिर उदार बा, इकोनॉमी में 9 परसेंट के उछाल बा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान बा, 4जी के बाद अब 5 जी आवत बा, पोस्ट ऑफिस में एटीएम बा। पूर्वांचल के विकास बा और एकरो से मन न भरल, तो प्रधान मंत्री के जवाब बा।

माननीय महोदया, इस बजट के समर्थन और वर्णन के लिए दो शब्द काफी हैं - गति और शक्ति। इस देश की आजादी के 75 साल से 100 साल तक कैसे आगे बढ़ना है, इस बजट में हम वह भी देख सकते हैं और बजट में इस सरकार की आर्थिक गतिविधियों, नीतियों की निरंतरता भी देख सकते हैं। इस यथार्थवादी बजट के लिए मैं विशेष रूप से सरकार और वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ।

महोदया, वे दिन लद गए, जब चुनाव के समय बजट का उपयोग चुनावी मुद्दों के लिए किया जाता था। अब हमारा लक्ष्य कहीं और है और उस लक्ष्य की ओर हम हर कदम उठा रहे हैं। यह बजट भी अपने उसी इरादे और सार में स्पष्ट है। यह कहना कि यह बजट आने वाले 25 वर्षों के लिए एक vision प्रदान करता है, गलत नहीं होगा। एक भरोसे पर आधारित शासन मॉडल है, जिसे भारत इस बजट के माध्यम से देख रहा है। महोदया, हमने न केवल इस संकट के समय में जान बचाई है, बल्कि हमने जहान भी बचाया है। इसकी सराहना करने के लिए साहस चाहिए, जो मैं विपक्ष में नहीं देख रहा हूँ। उनके पास इस साहस की भी कमी है। मैं तो यहाँ कुछ आँकड़े बोलना चाहता हूँ, जैसा सब बोलते हैं कि आँकड़े झूठ नहीं बोलते। महोदया, यह कहानी है 70 साल की, 7 साल की और 17 साल की। करीब-करीब 70 साल एक राज था, 7 साल से हमारा राज है और आगे आने वाले 17 साल की हम कल्पना कर सकते हैं। आप भी कल्पना कर सकते हैं, तो कीजिये। महोदया, 70 साल में हमारा Foreign Exchange Reserve 300 billion dollars था, अब 7 साल में हमने इसमें 335 billion dollar जोड़ा है। आपने 70 साल में 70,000 kilometres National Highway बनाया, हमने सिर्फ 7 साल में 50,000 kilometres बनाया। आपने 70 साल में 40 करोड़ बैंक अकाउंट्स बनाए, हमने सिर्फ 7 साल में 43 करोड़ बनाए। आपने 70 साल में 7 AIIMS बनाए, हमने केवल 7 साल में 8 बनाए। Engineering Colleges, IIIT, आपने 70 साल में 5 बनाए, हमने बनाए बीस. 'Access to tap water', हर घर में नल से जल, आपने पहले 70 साल में मात्र 30 प्रतिशत को दिया, जबकि आज हमने उस rural में 13 प्रतिशत को मात्र 7 प्रतिशत में जोड़ दिया। पक्का घर, जो आपने 2011 तक 55 प्रतिशत बनाया, हमने इस 7 साल में 16 प्रतिशत बनाया। हर व्यक्ति को घर, नल, जल, सब कुछ देने का हमारा वादा है और हम उस स्पष्ट लक्ष्य के साथ बढ़ रहे हैं। हम कहते हैं कि यदि 70 साल तक आप हमसे आधी speed से भी काम करते, तो कल्पना कीजिए कि हमारा देश अभी कहाँ होता! लेकिन यह दायित्व और यह भाग्य हमारा है कि यह सरकार आई है, जो स्पष्ट लक्ष्य के साथ गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, उनके न्यूनतम living standard को बढ़ाने के लिए बहुत specific और time bound programme के साथ, एक particular speed के साथ काम कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 70, 7 और 17 में जब 17 पूरा होने वाला होगा, तो मान कर चलिए कि आपके सारे रिकॉर्ड टूट जाएँगे और हम कल्पना नहीं कर सकते कि 17 वर्ष के बाद हम कहाँ होंगे!

महोदया, बार-बार इस सदन में दो परिवारों का नाम लिया जाता है, as if यह सरकार उनके लिए काम कर रही है। उसका कोई औचित्य नहीं है। जैसा मेरे साथी, एल्फोंस साहब ने बताया कि यदि पूँजीवाद गलत है, तो मैं बता दूँ कि हमारे प्रधान मंत्री को बोलने में कोई संकोच नहीं 'that this Government has no business to be in business.' वे साफ यह बोलते हैं और उसके परिणाम दिख भी रहे हैं। यदि पिछले सात सालों में नहीं, पिछले दो सालों में इस देश में 44 unicorn पैदा हो गए, तो यह कोई इत्तिफाक नहीं है, इसके पीछे एक सोच है।

महोदया, मैं अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि हम इस तरह के हज़ारों युवाओं के साथ चल रहे हैं और हज़ारों परिवारों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो केवल मात्र एक ही परिवार के लिए काम कर रहे थे। 70 साल तक इन्होंने एक भ्रम बना कर रखा और देश को ये एक ऐसी दिशा में ले जा रहे थे, जिसका न तो कोई भविष्य नज़र आता था और न ही कोई अंत नज़र आता था।

2.00 P.M.

महोदया, दुनिया की एक बड़ी कंपनी है, जिसका पूरे वर्ल्ड में नाम है, वह है - Cisco. यह कम्पनी IT hardware के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती है और उसके प्रमुख ने जो बातें कही हैं, मैं उनको जरूर क्वोट करना चाहता हूं, खासकर उन लोगों के लिए, जो हमारी नीयत पर शक करते हैं। उन्होंने कहा है, "Being the hottest global market in both listed and unlisted worlds, India is on a roll. If I am betting on one country in Asia, it is India. और उससे भी महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही, वह है," But if I am betting on two countries in Asia, then it is India and India."

महोदया, हमारे साथी, मनोज भाई बिहार से आते हैं, जो प्रोफेसर हैं। हम सबको मालूम है कि नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी थी, जिसको बख्तियार खिल्जी ने तहस-नहस कर दिया था, बरबाद कर दिया था। 2014 तक उसके पुनरुद्धार की क्या स्पीड चल रही थी, यह देश से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन 2014 से लेकर अब तक, इन सात सालों में वह यूनिवर्सिटी फिर से phoenix की तरह राख के ढेर से उठ कर खड़ी हुई है। मैं उम्मीद करता था कि अपने ही क्षेत्र की प्रशंसा में अगर आप दो शब्द बोल देते, तो हम लोगों का कलेजा भर जाता कि चलो, कम से कम एक व्यक्ति ने तो अपने क्षेत्र के बारे में हमारी तारीफ भी की है। हम भी तारीफ चाहते हैं, आपसे तारीफ चाहते हैं और यह कोई गलत भी नहीं है। डेमोक्रेसी में आप हमारा criticism कीजिए, जरूर कीजिए, लाख बार कीजिए, लेकिन ये सब जो आंकड़े हमने बताए, उनको देखते हुए, यदि हमने एक भी अच्छा काम किया हो, उस पर आप अगर एक शब्द भी बोल देते, तो मेरे जैसे नये लोगों को थोड़ी सांत्वना मिलती।

महोदया, पिछले दो बरस बहुत चुनौतीपूर्ण थे, यह हम सबको मालूम है और इस बात को सारे लोगों ने स्वीकार किया है। मैं श्री चिदम्बरम जी का बहुत सम्मान करता हूं, वे वित्त मंत्रालय के साथ-साथ और भी कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्होंने इस बजट के संदर्भ में एक बात कही कि हमें context को समझने की जरूरत है, संदर्भ को समझने की जरूरत है। मुझे यह सुन कर दुःख हुआ कि इन दो सालों के पीरियड में हम जिस चुनौतीपूर्ण वातावरण से गुज़र रहे थे, उसके context को उन्होंने समझा ही नहीं और इस चुनौतीपूर्ण समय को जोड़ कर उन्होंने अपनी बात नहीं कही। उन्होंने तो सारी चीजों को सामान्य मान कर अपने तुलनात्मक आंकड़े दिए और चुनौतीपूर्ण context को बिल्कुल ही भुला दिया, बल्कि ऊपर से वे हमें ही समझा रहे हैं कि context को समझना चाहिए, context की बात करनी चाहिए।

महोदया, पिछले साल लगभग इसी समय में इस सदन में श्री देरेक ओब्राईन जी ने IIMA Professor, Shri Chinmay Thumbe द्वारा माइग्रेशन पर एक पुस्तक का उल्लेख किया था, उस पुस्तक को पढ़ने की सिफारिश भी की थी। मैं विपक्ष को याद दिलाऊँगा कि इसी लेखक ने महामारी के सम्बन्ध में फिर से एक लेख लिखा और बताया कि पहले हुई तीन महामारियों में भारत ने लगभग चार करोड़ लोगों को खो दिया था, लेकिन अब भूख से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। आज जब हम चुनौती से निकल रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में विश्वास न करने का कोई औचित्य ही नहीं है।

कल श्रीमान कपिल सिब्बल जी ने अभी चल रहे 'अमृत काल' को 'राहु काल' कहा। मुझे संदेह है कि क्या उनका मतलब बुरे समय को दर्शाने के लिए 'राहु काल' कहने से था?

"जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।"

उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी पार्टी के साथ देश क्या कर रहा है, यह हम सबको मालूम है, लेकिन यदि इसमें उनको 'राहु काल' नज़र आ रहा है, तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Hon. Member, you have to conclude now.

श्री महेश पोद्दार : बस मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

महोदया, विपक्ष बेरोज़गारी के स्तर पर जम कर हंगामा कर रहा है, लेकिन मेरे सारे साथियों ने एक से बढ़ कर एक आंकड़े दिए, विशेषकर 7.5 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश और राज्यों में 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश के संदर्भ में। इन आंकड़ों को देखने के बाद मैं समझता हूं कि बेरोज़गारी के बारे में बात करना उचित नहीं है और यदि आप इसके संदर्भ में सोचें, तो मैं समझता हूं कि हमारी नीयत पर आपको शंका नहीं करनी चाहिए।

महोदया, विपक्ष ने MSME की दुहाई दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं स्वयं इसी क्षेत्र से आता हूं और मैंने इस क्षेत्र को जिया है, इसका नेतृत्व भी किया है, इसलिए मैं इस क्षेत्र से वाकिफ़ हूं। अब तक सिर्फ बहुत छोटे समय के लिए पॉज़ हुआ था, लेकिन वापस जिस तरह से यह क्षेत्र खड़ा हुआ है, मैं समझता हूं कि मेरे साथियों को उसके बारे में भी तारीफ करनी चाहिए थी, चाहे इसके साथ वे वित्त मंत्री को कुछ सुझाव भी दे देते। अंत में, मैं इस बजट को अपना समर्थन देता हूं। यह बजट विभिन्न आयामों में संभावनाओं के भविष्य को अपनाते हुए अतीत को स्वीकार करने में सफल रहा है। सरकार ऊंचा लक्ष्य रखने से नहीं कतराती है और यही वह नया भारत है, नया साहस है, जिसकी इस समय हमें जरूरत है, धन्यवाद।

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश) : माननीय महोदया, मैं सच्चाई के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। कल से मैं सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की बातें काफी गम्भीरता से सुन रहा था। माननीय मोदी जी ने यह तक कह दिया कि इस देश में बेरोजगारी है ही नहीं, हमारे बजट के हर पन्ने में रोजगार है और आंकड़ों के माध्यम से ऐसा बता दिया कि यहां रामराज्य है, यहां किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है। मैं सदन को सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं :

"इनकी फाइलों में गावों का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे और दावा किताबी है,
इनके मेज चांदी के और जाम सोने के,
मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है।"

महोदया, मैं आगे कहना चाहता हूंः

''कोई चैन से सो रहा है देश बेचकर,
कोई सुहाग बचा रहा है मंगलसूत्र बेचकर,
बाप ने उम्र गुज़ार दी घर बनाने में'
बेटा उसकी सांस खरीद रहा है घर बेचकर,
बरबाद हो गये कई घर दवा खरीदने में,
कुछ की तिजोरी भर गई ज़हर बेचकर।''

महोदया, बजट किसी भी सरकार के काम-काज और वित्तीय प्रबंधन के बीते कल का इतिहास, वर्तमान का आईना और आने वाले कल का मील का पत्थर होता है। बजट के बारे में चाणक्य ने कहा था - ''जो प्राप्त न हो, उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त है, उसे संरक्षित करना और जो संरक्षित है, उसे समानता के आधार पर जन कल्याण में खर्च करना।''

''प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम्।
नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रिय हितम्।''

प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है, प्रजा के हित में ही राजा को अपना हित देखना चाहिए। जो स्वयं को प्रिय लगे, उसमें राजा का हित नहीं है। यह चाणक्य की नीति है।

महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि हमारी योजना, हमारा बजट ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसे भी उसका लाभ मिले, यह गांधी जी का विचार था।

'अमृत महोत्सव' काल का बजट में बड़ा गुणगान किया गया है। मैं संक्षेप में कहना चाहता हूंः

''इसमें अमृत पी गये अडाणी जी और जनता पीये हलाहल,
जबकि यहां सदन में बैठे-बैठे सांसद करें कोलाहल।''

इस बजट में चाणक्य, तुलसी और गांधी जी के विचारों की कोई झलक नहीं है। हमारे देश के अन्नदाता, किसान, बेरोजगार, नौजवान तथा रोज़ी-रोटी खोने वाले गरीब, पिछड़े और दलितों का भी कोई भविष्य नहीं है।

महोदया, एफसीआई पर 51.83 अरब डॉलर का कर्जा है, वह दिवालिया होने के कगार पर है, जो इस देश के गरीबों का पेट भरता है। बजट में पुराने वादों और कामों के हेडिंग, क्रम और नाम बदल कर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है और कुछ पुराने वादों का उल्लेख भी नहीं किया गया है। मोदी जी ने 2017 में कहा था कि 2022 तक नया भारत बनेगा।

और अब 25 साल बाद बनेगा, ऐसी बात कही जा रही है। वर्ष 2022 तक 22 हजार मंडियों को eNam से जोड़ने, वर्ष 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने तथा वर्ष 2015 के बजट में भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में तीन-तीन करोड़ मकान बनाने का वायदा किया गया था। वर्ष 2015 में

भी डेढ़ लाख पोस्ट ऑफिसों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने की बात कही गई थी, स्मार्ट सिटी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, बुलेट ट्रेन का वायदा, अच्छे दिनों का सब्ज़बाग, 100 सैनिक स्कूल खोलना, गंगा की सफाई जैसे पुराने मुद्दों का कोई हिसाब नहीं है, इन नई घोषणाओं का क्या होगा, भगवान जानें। इस अमृत काल के बजट में 'मनरेगा' जैसे महत्वपूर्ण कार्य के बजट में कटौती, शिक्षा, स्वास्थ्य के बजट में कटौती, गैस, पेट्रोलियम की सब्सिडी में 4,000 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। खाद में कोई छूट नहीं, इन्कम टैक्स में कोई छूट नहीं। आप सच्चाई को छिपाकर कितने दिन गुमराह करते रहेंगे। किसी ने कहा है उसे भूलें नहीं किः

'उमंगों की नदी बहती किसी दिन सूख जाती है,
कभी होता जो अपना है वही अनजान होता है।
कहो इन जुमलेबाजों से ये छिपायें नहीं सच को,
तिलक के अक्षतों में भी लिखा वनवास होता है।'

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, वास्तव में यह भारत के 'अमृत महोत्सव' काल का बजट ही नहीं है, बल्कि यह इंडिया का बजट है, जो कि नागपुर में लिखा गया है, दिल्ली में छापा गया है और माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में पढ़ा गया है, जिसे कॉरपोरेट द्वारा सराहा गया है और जिसका जुमलेबाजों के द्वारा मेजें थपथपाकर स्वागत किया गया है। यह ऐसा बजट है, जिसमें भारत नहीं बल्कि इंडिया की झलक दिखाई देती है।

'अब इस मुल्क की बरबादी के आसार नज़र आते हैं,
अब दिल्ली की हुकूमत पर बैठे हुए तानाशाह नज़र आते हैं।
जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू की तो हमने दिया, किसानों ने दिया,
अब इन हुक्मरानों को ही किसान, पाकिस्तानी-खालिस्तानी नज़र आते हैं।"

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया,

'शोहरत की फिज़ाओं में इतना न उड़ो यारो,
परवाज़ न खो जाए कहीं ऊंची उड़ानों में।'

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, इस देश का अन्नदाता किसान, धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा कर दुनिया का पेट भरता है। इसी का एक बेटा सरहद में सीने पर गोली खाकर देश की रक्षा करता है। यह वही अन्नदाता है, जो हमारी जीडीपी को बढ़ाता है, इसी की मेहनत से मंदिरों में भोग लगते हैं, लेकिन यही अन्नदाता जब अपनी फसल का दाम मांगता है, तब उसे गोलियों से भून दिया जाता है और गाड़ियों से कुचल दिया जाता है। मंदसौर और लखीमपुर खीरी इसका उदाहरण है, जिसे सब जानते हैं। यही किसान तानाशाही सरकार से निराश होकर काले कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करता है और एक वर्ष के आंदोलन के दौरान 700 किसान शहीद हो जाते हैं। किसानों को कितना प्रताड़ित और अपमानित किया गया है, इसे दुनिया के लोगों ने देखा है। किसानों को भगवान कहने वाली सरकार के पास

शहीद किसानों के लिए संवेदना का एक शब्द भी नहीं होता है! यह कैसी सरकार है कि अगर विपक्ष द्वारा किसानों का समर्थन किया जाता है, काँग्रेस के द्वारा समर्थन किया जाता है, तो उन्हीं के ऊपर गुमराह करने का आरोप लगाया जाता है, झूठे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन एक वर्ष के बाद इस तानाशाह सरकार को सच्चाई के सामने झुकना पड़ता है और इस काले कानून को वापस लेना पड़ता है। किसानों ने साबित कर दिया कि:

'किसानों के भी सीने पर छिपे अरमान होते हैं,
मचल कर जब निकलते हैं तो वे तूफान होते हैं।'

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मोदी जी ने दो करोड़ युवाओं को रोजगार का वायदा किया था और उनके द्वारा रोजगार मांगने पर उन्हें पकोड़ा तलने की सलाह दी थी। इस देश के युवाओं का, उनकी योग्यता का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है! युवा शक्ति का सम्मान कीजिए, अपमान करने से भारत नहीं बनेगा।

महोदया, इस देश की युवा शक्ति का सम्मान तो आदरणीय राजीव गाँधी जी ने किया था। उन्होंने युवाओं को, इस देश को एक नई टेक्नोलॉजी दी, उन्होंने इस देश के नौजवानों पर विश्वास किया, 18 वर्ष के नौजवानों को मताधिकार दिया और कहा, हमें तुम्हारी ताकत पर भरोसा है, विश्वास है, जाओ, किस तरह का भारत बनाना चाहते हो - यह हुँकार राजीव गाँधी जी ने दी थी, जो इस देश के नौजवानों का सम्मान था।

महोदया, आज नौजवान यह कहना चाहता है :
"सिसक रही है आज जवानी धन कुबेर की बाँहों में,
अश्रु बहाता पड़ा कृषक है फुटपाथों की गोदी में।
नवयुवको, धिक्कार है तुमको, खून नहीं क्या धमनी में,
चूर-चूर कर दो घमण्ड को,
और शोषक की बाँहों को, शोषित की बाँहों से।"

महोदया, आज देश पर 1,36,000 मिलियन डॉलर का कर्जा है। देश में 10 फीसदी बेरोजगारी बढ़ी है, 42 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 37 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने के लिए विवश हैं। देश में 33,24,000 बच्चे अत्यंत कुपोषित हैं। आज भी कई सुदूर पिछड़े इलाकों में बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं। एसटी के 28 प्रतिशत, एससी के 21 प्रतिशत और ओबीसी के 20 प्रतिशत बच्चे अत्यधिक कुपोषित हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : ऑनरेबल मेम्बर, अब आप conclude कीजिए।

श्री राजमणि पटेल : महोदया, भारत में 6 लाख छोटे उद्योग बंद हो गए, जिसके कारण लाखों लोग बेरोजगार हो गए। आज 60 लाख पद खाली हैं। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग में 8 लाख पद खाली हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे विभाग में पद खाली हैं, वे पद भरे नहीं जा रहे हैं। हमारे

बेरोजगार नौजवान ओवर एज हो रहे हैं, सरकार द्वारा नए पद सृजित नहीं किए जा रहे हैं। एक तरफ 60 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ पद भरने का विज्ञापन निकलता है, करोड़ों रुपए वसूल लिए जाते हैं, लेकिन परीक्षा नहीं होती है। यदि परीक्षा होती है, तो रिजल्ट नहीं आता है और यदि रिजल्ट आ जाता है, तो नियुक्ति नहीं होती है। इस बजट में झूठे वादे और जुमलों के अलावा कुछ नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : धन्यवाद, पटेल जी। अब मैं अगला नाम पुकारती हूँ।

श्री राजमणि पटेल : महोदया, यूपीए सरकार में थोड़ी-सी कीमत बढ़ती थी, तो 'महँगाई डायन' का गाना गाया जाता था।...(**समय की घंटी**)... आज महँगाई चरम पर है, तो बोलती बंद है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Patel ji, please conclude now. I have to call the next Speaker.

श्री राजमणि पटेल : महोदया, मैं एक कवि की बात के माध्यम से यह कहना चाहता हूँः

*"पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी, गैस आठ सौ पार" ...(**व्यवधान**)...*

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : धन्यवाद, पटेल जी। श्री रामकुमार वर्मा जी। Sorry, Sorry, your time is over.

श्री राजमणि पटेल : *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Nothing will go on record. I have called the next speaker. श्री रामकुमार वर्मा जी।

श्री राजमणि पटेल : *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Nothing is going on record.

श्री राजमणि पटेल : *

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) **:** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे केन्द्र सरकार और वित्त मंत्री महोदया ने 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया है, उस पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। चूँकि बजट पर

* Not recorded.

हमारे सत्ता पक्ष की तरफ से और उधर से भी बहुत सारी बातें हो गई हैं, इसलिए मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूँगा। 2014 के बाद जो भी बजट आया, उसका उद्देश्य, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी का जो यह संकल्प और प्रतिबद्धता है कि देश का micro level से आर्थिक विकास हो और देश समृद्ध बने, जो अपनी परंपरागत अर्थव्यवस्था है, वह उसको संचालित करे, लेकिन आधुनिकता के साथ वैज्ञानिक तरीके से उसका यूज़ करते हुए हमारा न्यू इंडिया, नव भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का जो संकल्प है, उसको इस बजट के माध्यम से प्रतिबिम्बित किया गया है।

महोदया, मैं बजट पर बोलने से पहले आपसे एक-डेढ़ मिनट जरूर लूँगा। मैं राजनीति नहीं करूँगा, बजट पर ही बोलूँगा, लेकिन हमें मजबूर किया गया है। कल राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर प्रधान मंत्री जी का जो वक्तव्य था, धन्यवाद के रूप में उनका उद्बोधन था, उस पर आज भी चर्चा हुई और कहा गया कि प्रधान मंत्री जी बजट की बात को कहीं और लेकर चले गए, बजट में कहा कि काँग्रेस नहीं होती, तो यह होता या काँग्रेस होती, तो यह नहीं होता। महोदया, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा। हमारे विपक्ष में बहुत विद्वान साथी हैं, उन्हें राजनीति का अनुभव है। मैडम, मेरे पास कितना समय है?

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : आपके पास दस मिनट हैं।

श्री रामकुमार वर्मा : सत्ता के अंदर उन्हें पचासों वर्षों का अनुभव है। हमारे विपक्ष के एक most senior साथी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को देखा और कहा कि इसमें कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक औपचारिकता के रूप में प्रकट किया गया है। देश का नक्शा नहीं है, कुछ नहीं है। मैं उनसे यही अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वे उसके 74वें प्वाइंट को सरसरी निगाह से देखें और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसी भी बात के लिए साबित कर दें कि यह गलत है, मैं सोचता हूँ कि उनके लिए तब यह कहना ठीक रहेगा। इतना ही नहीं, उसी पार्टी के हमारे एक वरिष्ठ नेता ने तो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ही question mark लगा दिया कि यह अभिभाषण क्या है, यह राष्ट्रपति जी को पेश ही करना था! महोदया, मैं आज आपके माध्यम से इस सदन को इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि देश के राष्ट्रपति और देश के प्रधान मंत्री के संबंध में ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें तैयार करके दे दे और उसके अनुसार काम चले। यह परंपरा उनकी रही होगी और रही भी है, जिसके रिजल्ट उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। राष्ट्रपति जी एक गरीब परिवार से हैं। वे अपनी दक्षता-प्रतिभा के साथ और अपनी क्षमता के आधार पर इस देश के राष्ट्रपति बने हैं। प्रधान मंत्री जी गरीबी के वातावरण को देखते हुए, पूरे देश की स्थिति क्या है, उसे देखते हुए, आज प्रधान मंत्री के रूप में हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि इन्हें संदेह नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है और वित्त मंत्री महोदया के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसे ये गंभीरता से लें। यह देश के आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा बजट है, मैं इसका अभिनंदन करता हूँ।

महोदया, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में मेरे सम्माननीय सांसदों ने बोला है। उनके लिए कहा गया कि महामारी नहीं थी। प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सौ वर्ष के बाद इतनी बड़ी महामारी आई है। महामारी में देश एक होता है और जब देश एक होता है, तब निश्चित है कि चाहे लड़ाई महामारी से हो या विदेशी व्यक्ति से हो, उससे मुकाबले के लिए देश एकजुट है। प्रधान मंत्री

जी ने महामारी आने के बाद देश से आह्वान किया। मैं बताना चाहता हूँ कि कितना बड़ा विश्वास था। उन्होंने आह्वान किया, बिना लॉ एंड ऑर्डर के जनता कर्फ्यू घोषित किया गया और जनता ने विश्वास प्रकट किया, लेकिन मेरे विपक्ष के लोगों को यह एक नाटक लगा। वे लॉकडाउन और अन्य बातों को लेकर चले और इस महामारी के अंदर इस देश की जान को भी बचाया और जहान को भी बचाया। जो यह कह रहे हैं कि इस बजट से रोजगार नहीं मिलेगा, यह नहीं होगा - महोदया, मैं बजट के आंकड़ों के बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इस महामारी में आज 170 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। हमने वैक्सीनेशन और फार्मा के द्वारा 150 देशों को सहायता दी। यह एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है और गर्व करने का विषय है। अगर वे इस पर धन्यवाद भी प्रकट करते, तो अच्छा होता। मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री जी की यह सोच देखिए कि किसी भी मुख्यमंत्री ने सौ में से दो बातें भी अच्छी कहीं, तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की।

यहाँ पर विपक्ष की सांसद महोदया ने कहा कि हमारे मुख्य मंत्री की प्रशंसा की, हमने सहयोग दिया। हम यह मानते हैं कि जो करीब 135 करोड़, 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसने साथ दिया। प्रधान मंत्री जी के लिए क्या-क्या कहा जाता है, लेकिन उसको सहन करते हुए उन्होंने आज देश को इस महामारी से बचाने के बाद देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाया। अभी बजट के अंदर बताया गया है कि हमारी आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो यह कम नहीं है। मैं यह गर्व के साथ कहता हूँ। विपक्ष वाले तुलना कर रहे थे और हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि साहब, यह खर्च कम कर दिया गया, बजट कम कर दिया गया। अगर वे वर्ष 2013-14 के साथ इसकी तुलना करते, तो मालूम पड़ता कि यह बजट कितना प्रोग्रेसिव है और अभी भी यह प्रोग्रेसिव है। मैं कहता हूँ कि यह 9.2 प्रतिशत का अनुमान दर्शाता है कि हमारा विकास विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक गति से होने वाला है। आज 14 क्षेत्रों में 60 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। एक पार्टिकुलर PLI स्कीम के तहत 60 लाख रोजगार देने की बात कही गई है। जो Production Linked Incentive Scheme लागू की गई है, उसमें इंसेंटिव दिया जाएगा। उसके अंदर हमने 14 सेक्टर्स को सेलेक्ट किया है। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो जॉब्स क्रिएट करेंगे, उनमें टेक्नोलॉजी का इन्क्लूज़न होगा और वह हमारे कैपिटल का भी हिस्सा होगा। उसके द्वारा जॉब तो मिलेगी ही, उससे हमारे एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी होगी। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के संबंध में वर्ष 1992 के आस-पास देश की जो स्थिति हुई, तब सारे विद्वान लोग थे और इतनी बड़ी महामारी भी नहीं थी, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट का वन बिलियन रहना और एक सप्ताह का भी भुगतान नहीं होना इस बात को दिखाता है कि उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या हालत रही होगी। तब हमें गोल्ड भी गिरवी रखना पड़ा था। अब वैसी स्थिति नहीं होगी और बहुत ही सॉलिड तरीके से अर्थव्यवस्था चलेगी। इतना ही नहीं, PLI स्कीम से 60 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है, लेकिन उसके अलावा 30 लाख एडिशनल रोजगार भी मिलेंगे। ये कहते हैं कि साहब, रोजगार का तो कुछ हिसाब-किताब ही नहीं हुआ। उनको दो करोड़ की बात याद आई और उन्होंने कहा कि यह उनका एक चुनावी नारा है। माननीय महोदया, मैं कहता हूँ कि उधर की पाठशाला ऐसी हो गई है, ...(**समय की घंटी**)... जिस पार्टी का इतिहास इतना अच्छा था, आज़ादी की लड़ाई का सारा श्रेय वे लेते हैं, लेने दो, उसमें हम सब शामिल थे, लेकिन उनकी

पाठशाला में आज यह हो रहा है कि इस असत्य को पूरे देश में फैलाओ, लोग भ्रमित हों और उनके भ्रमित होने के बाद वे सत्ता में आएँ। प्रधान मंत्री जी ने अच्छी सलाह दी है।

मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि इस बजट के अंदर 39.45 लाख करोड़ का जो expenditure है, उसमें करीब 13 परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम 2020-21 की बात करें, तो ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : अब आप कन्क्लूड करें, प्लीज़। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामकुमार वर्मा : मैडम, अभी तो दो-तीन मिनट बाकी हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : अभी आपके पास एक मिनट का समय है।

श्री रामकुमार वर्मा : मैडम, दो-तीन मिनट और दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : दो-तीन मिनट नहीं, आपके पास केवल एक मिनट है।

श्री रामकुमार वर्मा : मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने इस तरह से fiscal और revenue deficit को कंट्रोल किया। महँगाई की बात करें, तो वह अब डबल डिजिट पर नहीं आएगी। गरीब कल्याण के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' से लेकर डिजिटल के माध्यम से हमारी यूनिवर्सिटीज़ और ... (**समय की घंटी**)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : धन्यवाद, वर्मा जी। You have to conclude.

श्री रामकुमार वर्मा : मैडम, एक मिनट, मैं अभी खत्म करता हूँ।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : सॉरी, मैंने आपको पहले ही अवगत कराया था। ...(**व्यवधान**)... श्री सैयद नासिर हुसैन जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री रामकुमार वर्मा : डिजिटल नोट के माध्यम से 47 करोड़ को जो लाभ मिला, अब उसका लाभ एजुकेशन में भी मिलेगा तथा गरीब और ग्रामीण के लिए मिलेगा। फाइबर नेटवर्क के द्वारा उनको 'एक चैनल, एक कक्षा' के आधार पर जो 200 चैनल्स होंगे, उनको उसका भी लाभ मिलेगा। गरीब को रोजगार मिलेगा, वह समृद्धशाली हो रहा है और रहेगा। आप कम से कम असत्य बोलना बन्द करें, सच्चाई पर चलें। आप अपना मंथन शुरू करें, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती वंदना चव्हाण) : धन्यवाद, वर्मा जी। श्री सैयद नासिर हुसैन जी।

श्री सैयद नासिर हुसैन (कर्नाटक) **:** मैडम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज बजट पर अपनी बात रखने का मौका दिया।

बजट से हमारे देशवासियों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत ही निराशाजनक बजट आया है। सत्ता पक्ष के लोग जब बार-बार बजट पर चर्चा कर रहे थे, बार-बार खड़े हो रहे थे, तो हमारे कलीग और हमारे नेता रिपुन बोरा जी की बात मुझे याद आ रही थी और सच लग रही थी कि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए ये बार-बार कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे थे। इनके लिए 2022 टारगेट ईयर था। इनको 2022 तक देश को स्मार्ट सिटीज़ देनी थीं, इनको 2022 तक बुलेट ट्रेन देनी थी, इनको 2022 तक पूरे हिन्दुस्तानियों को घर देना था, मकान देना था। वर्ष 2022 में हमारे किसानों की आय दुगनी करनी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसीलिए चाहे Motion of Thanks हो या बजट हो, चाहे उस हाउस में हों या इस हाउस में हों, आपने लगातार कांग्रेस को कोसने का काम किया। हम आपकी बात मान लेते हैं कि कांग्रेस सिर्फ oppose करने के लिए oppose कर रही है, आपकी यह बात भी मान लेते हैं कि कांग्रेस असत्य बोल रही है, लेकिन आप यह बताइए कि आज हिन्दुस्तान की सड़कों पर एक करोड़ युवा आरआरबी के एग्ज़ाम में पर्चा भरते हैं और नौकरी के लिए सड़क पर उतरते हैं, तो क्या वे असत्य बोलते हैं? अगर आज छात्र सड़कों पर उतर रहे हैं तो क्या वे असत्य बोल रहे हैं? हिन्दुस्तान की राजधानी के बाहर जो किसान 14 महीने तक बैठे थे, क्या वे झूठ में वहां जाकर बैठे थे? अगर यह सूरते-हाल हिन्दुस्तान का है तो आप opposition parties को बार-बार क्यों कोसते रहते हैं?

मैडम, यहां कोविड की बहुत चर्चा हुई, यहां क्लेम किया गया कि हमने कोविड के समय में ऐसा काम किया, वैसा काम किया। यहां पर यह बोला गया कि दुनिया भर में अगर किसी देश में सबसे ज्यादा काम हुआ तो वह हिन्दुस्तान में हुआ, यह दावा हो रहा था, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन किया, जिस तरह के scenes, जिस तरह के visuals हिन्दुस्तान में देखने को मिले, मुझे लगता है कि partition के बाद जो दो बार इस तरह के visuals देखने को मिले - एक तो नोटबंदी के समय देखने को मिला और दूसरा कोविड के समय देखने को मिला - जिस तरह से बड़े-बड़े शहरों को छोड़कर कामगार अपने गाँवों की तरफ जा रहे थे, छोटे बच्चों को अपने कंधों पर लाद कर ले जा रहे थे, बूढ़े माँ-बाप को अपने कंधों पर रख कर ले जा रहे थे, एक जवान लड़की अपने बूढ़े बाप को साइकिल पर बिठाकर हज़ारों मील दूर ले जाती है, एक छोटा बच्चा अपनी माँ की लाश के साथ खेलता रहता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम होता है कि उसकी माँ मर चुकी है - इस तरह के scenes हिन्दुस्तान में कभी देखने को नहीं मिले थे। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी फैलाई, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोविड फैलाया। आज मैं कांग्रेस का एमपी होने के नाते फ़ख के साथ कहना चाहता हूं कि उन बेबस, बेसहारा लोगों को कांग्रेस के एक-एक आदमी ने ज़मीन पर उतर कर उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है, उनको सहारा देने का काम किया है, उनको उम्मीद देने का काम किया है, उनको confidence देने का काम किया है। हम लोग बस, ट्रक्स और रेल गाड़ियां arrange करके इन लोगों को वापस अपने घर भेज रहे थे, हमें देखकर कर्णाटक की सरकार ने बसें और रेल गाड़ियां arrange कीं, गोवा की सरकार ने arrange कीं, गुजरात की सरकार ने arrange कीं, क्या वे लोग भी महामारी फैला रहे थे? याद रखिए, वहां पर आपकी ही सरकारें थीं। आप दूसरों पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है, उसको देश जानता है। इसके साथ ही आपको यह भी

जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि आप इस देश की सरकार हैं, आखिरकार इतनी तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग वापस अपने गाँव की तरफ क्यों जाना चाह रहे थे, जहां काम कर रहे थे, वहां से अपने गाँव वापस क्यों जाना चाह रहे थे? इसके दो कारण थे, उनको पता था कि वहां उनके लिए कोई गारंटी नहीं थी, न जॉब्स की गारंटी थी, न खाने की गारंटी थी, न ही शेल्टर की गारंटी थी, इसीलिए वे बेबस, बेसहारा होकर अपने रिश्तेदारों के पास अपने गाँव जाना चाह रहे थे। दूसरी तरफ उनको अपने गाँव में अगर एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी, तो वह 'मनरेगा' में नज़र आ रही थी। 'मरनेगा' की वजह से वे वापस जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहां उनको यदि कुछ जॉब्स की गारंटी दी थी, तो वह यूपीए की सरकार ने दी थी। आज प्रधान मंत्री जी यहां खड़े होकर कह रहे थे कि कोविड महामारी के समय में सरकार सफल रही। अगर कोविड महामारी के समय में आपकी सरकार थोड़ी-बहुत सफल रही तो वह सफलता 'मनरेगा' के कारण रही, जिसके बारे में आप बार-बार कहते हैं कि 'मनरेगा' आपकी विफलताओं का स्मारक है। उस विफलता के स्मारक ने आपका साथ देने का काम किया, लेकिन आज आप 'मनरेगा' के साथ क्या कर रहे हैं? वर्ष 2021-22 में आपने बजट में 35 परसेंट कटौती की, उसके बाद आपको 25 हज़ार करोड़ रुपये extra देने पड़ें, क्योंकि उसके बाद हिन्दुस्तान के कोने-कोने से लगातार आपके पास 'मनरेगा' में डिमांड आ रही थी। Revised estimates में 98 thousand crore हुए, अब वर्ष 2022-23 के बजट में आपने फिर उसमें कटौती करके 73 हज़ार करोड़ रुपये कर दिये, उसमें 13 हज़ार करोड़ रुपये के बिल्स पेंडिंग हैं। इसका मतलब है कि आपने मात्र 60 हज़ार करोड़ रुपये 'मनरेगा' के लिए रखे हैं। आपने उसमें कटौती की है।

हमने कोरोना के समय में बोला कि जो गरीब लोग हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, आप खरीदारी करने के लिए उनकी जेब में कुछ पैसे डालिए। आप यहां कहते हैं कि अगर दुनिया भर में सबसे सफल मैनेजमेंट था, तो वह हिन्दुस्तान की सरकार का था। आप थोड़ा देख तो लीजिए। ग्लोबली क्या हो रहा था, ग्लोबल सिचुएशन आप देख लीजिए। अमेरिका में डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया गया था, फ्रांस में किया गया था, कनाडा में किया गया था, यहां तक कि श्रीलंका और बंगलादेश में भी डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया गया था। गरीब लोगों को पैसा देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन 7.5 लाख करोड़ रुपये आप पूंजीपति दोस्तों के माफ कर देते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे होते हैं। ऐसी महामारी के टाइम पर, जब गरीब इस महामारी से जूझ रहा था, उस समय तीन करोड़ गरीब लोगों के जो राशन काड्र्स हैं, उन राशन काड्र्स को आप रद्द करने का काम करते हैं, ताकि उनको खाना भी न मिले, उनको पी.डी.एस. से कुछ सुविधाएं भी न मिलें।

बार-बार आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, अनइम्प्लॉयमेंट नहीं है। प्रधान मंत्री जी यह भी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी यू.पी.ए. के ज़माने में थी। आज सुबह मैं आंकड़े देख कर आ रहा हूं, 7.5 परसेंट बेरोजगारी हिन्दुस्तान में है। 2018 में 6.8 परसेंट थी और जब हम लोग 2014 में सरकार से बाहर आये, तब 5.6 परसेंट थी। 5.6 है या 7.1 परसेंट है, यह प्रधान मंत्री जी को हम लोगों को बताना पड़ेगा। प्रधान मंत्री जी ने यहां पर कहा, बहुत सारे लोग यहां पर खड़े होकर लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी नौकरियां क्रिएट की हैं, नौकरियां दी हैं। मैंने बहुत कोशिश करके, रिसर्च करके नाम ढूंढ़ने की कोशिश की कि किस-किस सेक्टर में इन्होंने नौकरियां दी हैं, किस-किस सेक्टर में इन्होंने नौकरियां क्रिएट की हैं, हमारे युवाओं को

इन्होंने कहां नौकरियां दी हैं। बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे कुछ थोड़ा बहुत मिला, यह थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया है। कुछ नौकरियां इन्होंने दीं, एक नया सेक्टर इन्होंने खोला। उस सेक्टर का नाम क्या है? उस सेक्टर का नाम vigilante sector है। इसके अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट्स क्या हैं, cow vigilante depatment, love jihad vigilante depatment, new year disruption vigilante depatment, valentine's day disruption vigilante depatment, anti-conversion vigilante depatment और लेटेस्ट हिजाब vigilante depatment भी चल रहा है। यहां पर इन्होंने युवा लोगों को लगा रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि हिजाब उनका Constitutional right है। इस देश में कौन लड़की क्या पहनेगी, क्या खाएगी, किसके साथ फिरेगी, कोई उसमें टोका-टोकी नहीं कर सकता है। जिस तरह मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन कर जाती हैं, उसी तरह से मेरी हिन्दू मां-बहनें भी घूंघट पहन कर जाती हैं। अगर उनके घूंघट पर भी आंच आएगी तो हम लोग उसी तरह लड़ेंगे, जिस तरह अब लड़ रहे हैं।

साथ में इन लोगों ने डिजिटाइजेशन की बहुत बात की है। इनके डिजिटाइजेशन में इन्होंने vigilante depatment को भी काफी डिजिटाइज़ किया है। ऐप्स तैयार करने के लिए इन्होंने लड़कों को छोड़ा है। सुल्ली ऐप्स और बुल्लीबाई ऐप्स जैसे आज भी ऐप्स क्रिएशंस होते हैं। फेक न्यूज़ फैक्टरी में कई लोग काम कर रहे हैं, ट्रोल आर्मी में कई लोग काम कर रहे हैं, आजकल हिस्ट्री रीराइटिंग के प्रोजेक्ट्स भी दिये जा रहे हैं। यहां पर इन्होंने युवा लोगों को लगा रखा है, ताकि देश के युवाओं का ध्यान न भटके और यहां पर युवा लोग नौकरियों की मांग न करें। ...(**व्यवधान**)... मैडम, मेरा टाइम अभी बाकी है, मेरे दो-तीन मिनट बाकी हैं।...(**व्यवधान**)...

अब मैं एमएसएमई पर आता हूं। 60 लाख एमएसएमई सेक्टर में यूनिट्स हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please start concluding.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Madam, MSME is the largest job provider, biggest 'Make in India' contributor. आज यह एक crisis में है, crisis में क्यों है- demonetisation की वजह से, faulty GST की वजह से और latest mismanagement of Covid crisis की वजह से। राहुल गांधी जी ने लोक सभा में inequalities की बहुत बात की है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please conclude; your time is over.

श्री सैयद नासिर हुसैन : मैडम, मुझे दो-तीन मिनट का टाइम दीजिए। मेरा टाइम 15 मिनट ओरिजनली था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Other Members from your party have consumed it.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Madam, I am the last Member from the Congress party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please speak quickly.

श्री सैयद नासिर हुसैन : यहां inequalities की बहुत बात हुई है। मैं उस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ डेटा दूंगा। Top one per cent is holding 33 per cent of national wealth, bottom 50 per cent holds 5.9 per cent of India's wealth. Top hundred richest people of India own as much as 55.5 percent of wealth. Top hundred richest people have so much wealth that they can fund India's primary and university education for next 25 to 30 years....*(Time Bell rings)*... cumulatively 142 people's wealth has increased from Rs. 23 lakh crores to Rs. 53 lakh crores.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Please conclude, Nasirji.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Madam, top two people's wealth has increased from 30.7 billion dollars to 175.5 billion dollars in the last two years.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): I will have to call the next speaker. ...*(Interruptions)*... You do not have time; you can see, you are already minus one. I have to call the next name.

SHRI SYED NASIR HUSSAIN: Madam, I was given 15 minutes; time is still left.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): That is true, but, time has already been consumed by the earlier Members. Please hurry up.

श्री सैयद नासिर हुसैन: मैं बहुत सारी बातें कहना चाह रहा था, लेकिन मैं सीधे किसानों की बात पर आऊंगा। दो दिन पहले प्रधान मंत्री जी इस सदन में खड़े होकर किसानों के बारे में बोल रहे थे। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Thank you, thank you. ...*(Interruptions)*.. I will have to call the next speaker. ...*(Interruptions)*.. Shri Abdul Wahab. ...*(Interruptions)*..

श्री सैयद नासिर हुसैन : किसानों ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, ...(**व्यवधान**)... लेकिन आपने किसानों के लिए क्या किया है? ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Nothing is going on record. ...*(Interruptions)*.. Nasirji, nothing is going on record. ...*(Interruptions)*.. Mr. Wahab, you please start.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): How can I start? ...*(Interruptions)*..

श्री सैयद नासिर हुसैन: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): It is not going on record. ...*(Interruptions)*.. Nasirji, it is not going on record. ...*(Interruptions)*.. Shri Abdul Wahab, please speak. ...*(Interruptions)*..

SHRI ABDUL WAHAB: How can I speak, Madam?

श्री सैयद नासिर हुसैन : *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): It is not going on record. ...*(Interruptions)*..

SHRI ABDUL WAHAB: I cannot speak. ...*(Interruptions)*.. How can I talk?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI VANDANA CHAVAN): Nasirji, thank you. Mr. Abdul Wahab. ...*(Interruptions)*..

SHRI ABDUL WAHAB: Madam Vice-Chairman, for any society or economy to thrive, we need peace and social harmony. That social harmony and peace first should be in the House, and then only we can conduct Business here. Just like that, peace and social harmony has to be there so that the economy thrives. That is why peace and harmony in the society is also required. Madam, I want to ask as to how the Government is disappointed if our opposition disrupts the House. You often remind us that the country is watching us. You often demand that the House should be in order for successful conduct of our Business.

Hon. Vice-Chairman, my first submission to the Government is that the country should be in order for the successful implementation of our Budget plans and its implementation. No company will invest when society is not in order. The

* Not recorded.

Government has good *mantras*, 'Beti Padhao and Beti Bachao', but I suspect its *karma*, *'Beti Darao, Beti Dhamkao'.*

(**उपसभापति महोदय** *पीठासीन हुए*)

I don't know the exact words. ...*(Interruptions)*.. Keeping Muslim women outside their colleges for their Naqab in Karnataka, I recollect the lyric written by Mumtaz Rashid and sung by Pankaj Udhas, 'निकलो न बेनकाब, ज़माना खराब है।' I think Mumtaz Rashid should change the lyrics as, निकलो न नकाब पहनकर, ज़माना खराब है।' So, I am not talking about this 'ghunghat' and all that because it is already mentioned. Otherwise, I am also supposed to be like this. ...*(Interruptions)*.. I am not using this one because already they have done it. ...*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please speak on the subject. ...*(Interruptions)*..

SHRI ABDUL WAHAB: If somebody is trying to do it, I will be the first one to die for my Hindu bahin. ...*(Interruptions)*..

श्री उपसभापति : प्लीज़, आप लोग आपस में बात न करें।

SHRI ABDUL WAHAB: Our Constitution ensures such a freedom of choice. Therefore, my second submission to the Government and this House is that we need to eradicate this hate economy from our country because it is a slow-poison to our country. It is as dangerous as corruption or black money is. Sir, this Budget speaks of a 25 years vision of Gati Shakti. I appreciate the Government's intention about the bright future for our country. I suspect this Budget will contribute towards our common goal. ..*(Interruptions)*..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your name will be called when your turn comes. Please go to your seat. ...*(Interruptions)*..

SHRI ABDUL WAHAB: I suspect that the Budget will contribute towards our common goal. For the future to be bright, the present should be in a good condition. I want to draw the attention of the Government to the wonderful opportunity of knowledge economy. It is a wonderful thing. But how it is to be implemented, for this you have to invest more in youth and education in Universities and all. Not like Gati Shakti, it is not possible without our proper knowledge economy. Shrimati Nirmala Sitharamanji

herself is a product of our prestigious JNU. Shri Jaishankar is also the product of JNU. Nobel Laureate in Economics, Shri Abhijit Banerjee, is a product of JNU. But, what is the prevailing condition of our country? ...*(Interruptions)*... Our students don't have subscriptions to international journals, articles and books. They have to use proxy websites for articles. They have to use proxy websites legions for books. Our university labs don't have enough instruments and chemicals to do research. Our university students and researchers today are in distress in poor hostels with no timely fellowships.

Mr. Deputy Chairman, Sir, our Economic Survey, 2021 informs that a number of primary and upper primary schools decreased by 15,000 in the year 2019. We only have sanctioned 50 universities in the same year. We need to build more quality schools, colleges, universities and research centres. Therefore, my third submission to the Minister, through this House, is to invest in our youth, in knowledge economy for a bright future and, in the next Economic Survey, I suggest you to add a new section on knowledge economy. ...*(Interruptions)*...

I appreciate the Government for its digital turn in this Budget, though it is too late. I suspect and am afraid about the increasing digital divide in the country. We should declare access to digital world the right to every Indian citizen, like we have the right to information and right to food. I request the Government to consider tax exemption for mobiles, computers and digital accessories to our students and research scholars.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time is over. You may say your concluding sentence.

SHRI ABDUL WAHAB: This Government, in 2014, came with a mantra -- 'बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार'। Eight years later, the Government is saying, 'gati shakti'! Thank you. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Sir, I thank you for the opportunity given to me to speak. This is a Budget which not only addresses the current challenges of the country but also prepares it to establish India as a global economic super power in the next twenty-five years. Sir, I would like to discuss a few issues that have been highlighted by my friends in the Opposition. They say that there is not much about unemployment that has been done in the Budget. I would like to show the mirror to our friends in the Opposition as to how unemployment rate has come down; in eleven months, this is the lowest; in the month of January, the unemployment rate is the lowest, according to the CMI data. Very conveniently they

quote the CMI data when it suits them and junk it when it does not suit their agenda. The last month data shows that it is only 5.4 per cent unemployment rate at the national level, but in the State of Rajasthan, this rate is as high as 16.9 per cent. In the case of other Congress-ruled States, I would like to give the numbers. Rajasthan is one of the highest in the country with 19 per cent unemployment rate! What are, these great financial wizards sitting in this House and the great Oxford-returned student in the other House, doing? Why can't they give this kind of wisdom to their own Government in Rajasthan, which is so close? They should spend their energies in giving employment in Rajasthan rather than spread rumours about this Government. In Uttar Pradesh, the unemployment rate is only three per cent. It is the CMI data. यह आपका डेटा है। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में केवल 3 परसेंट है, उत्तराखंड में 3.5 परसेंट है, गुजरात में केवल 1.2 परसेंट है, लेकिन बगल के राज्य राजस्थान में, जहां दुर्भाग्य से आपकी सरकार है, वहां 18.9 परसेंट unemployment rate है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि थोड़ा समय राजस्थान को दीजिए, अपनी wisdom को दीजिए। वहां जनता को शायद आपकी Oxford, Harvard की wisdom की ज्यादा जरूर है--हमें जरूरत नहीं है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। In eleven months, India's unemployment rate in January, 2022 was eleven months low. आप सारे न्यूज़ पेपर्स को पढ़ लीजिए, conveniently मत देखिए। Then they are masters in spreading this kind of false narratives to create an alarm. Let me tell you about an SBI's economist's survey report. It says "Credit Guarantee Linked Scheme that was announced as part of Covid package has saved 1.5 crore jobs in MSME sector and one crore in the micro sector alone." Therefore, I have busted your so-called unemployment barbs in this Government. It is you who are a poor performer. Please go to the States where you are in power and start delivering rather than simply giving us lectures. Secondly,... ...*(Interruptions)*....

श्री उपसभापति : प्लीज़, चेयर की अनुमति के बिना मत बोलिए। आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। प्लीज़, प्लीज़।

श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव : मैं एक NBER के बारे में ...(**व्यवधान**)... National Bureau of Economic Research (NBER) अमेरिका की एक प्रसिद्ध संस्था है, यहां सारी अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स पेपर्स सब्मिट करते हैं। Working Paper 29597 of NBER says, 'Inequality in India declined during Covid.' ...*(Interruptions)*.... यह पेपर है। ...(**व्यवधान**)... University of Chicago and three universities in US.... ....*(Interruptions)*... Inequality has reduced. ....*(Interruptions)*... Sir,... *(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nothing is going on record. Let him speak. ....*(Interruptions)*...

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO: Sir, these are facts. मैं यह बहुत conveniently...(**व्यवधान**)... कुछ रिपोर्ट्स को क्वोट करते हैं, I am quoting from India Inequality Report, 2018: Widening Gaps. What does it say? It says, 'Clearly, the richest in India have made their money through crony capitalism rather than through innovation or the fair rules of the market.' And they say, 'Classic examples of crony capitalism such as the 2G spectrum scam and the coal scam.' So is the case of real estate billionaires, many of whom benefited from cheap land allotted to them by your Governments. You are talking about some industrialists making it big. This happened very unfairly and through unethical methods when you were in power. Now you say, गरीब के ऊपर बहुत महंगाई की मार पड़ रही है। ...(**व्यवधान**)... अगर बहुत महंगाई की मार पड़ रही है, तो हमारी सरकार संवेदनशील है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो बड़े-बड़े नेता प्रधान मंत्री रहे हैं, 1974-75 में Indira Gandhi was the Prime Minister, उस साल का inflation 34.4 परसेंट था, एक साल का inflation 34.4 परसेंट था। ...(**व्यवधान**)... इनकी बोलती बंद हो जाएगी। In 1973-74, it was 21.5 per cent. एक साल में ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्य श्री सैयद नासिर हुसैन, आपकी सीट पर बैठकर बोलने की आदत बहुत गलत है। ....*(Interruptions)*.... You are not on your seat. Please keep quiet.

SHRI G. V. L. NARASIMHA RAO: So, poverty, inflation hurts the poor most. आपने सबसे बड़ा पाप अपने कार्यकाल में किया है। आज यू.एस. में चार दशक का सबसे ज्यादा inflation सात फीसदी है, हमारे देश में we are still around 5.2 per cent inflation. We are doing the best in the world. As hon. Prime Minister said, we are the fastest growing large economy with the lowest inflation. इसके लिए आप सबको माननीय मोदी जी की सराहना करनी चाहिए। आप सबको आकर मोदी जी को बधाई देनी चाहिए। आपको कहना चाहिए कि हमने अपने राज्य में जो पाप किया है, उसको हम सुधारेंगे। आपको कहना चाहिए कि मोदी जी, हम भी सुधारेंगे। आपके साथ हम भी चल पड़ेंगे। ...(**व्यवधान**)... Now let me address some questions that had been raised in my home State of Andhra Pradesh. मैं आपकी इजाज़त से इसको तेलुगू में बोलना चाहूंगा, मैं दो-तीन शब्द तेलुगू में बोलना चाहूंगा। * "First of all, I would like thank the hon. Prime Minister, Modiji, as the Centre is allotting funds

* English translation of the original speech delivered in Telugu.

three times more than the sanctioned amount to Andhra Pradesh for the last seven years. The Centre collected Rs.55,000 crore as GST and Direct taxes from Andhra Pradesh last year but it released more than Rs.75,000 crore to the State and I thank him for this. The Centre sanctioned funds to the State of Andhra Pradesh uder various schemes. Andhra Pradesh stands second for the funds received under MNREGA Scheme. More than 20 lakh homes were sanctioned to Andhra Pradesh under Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban). The people of Andhra Pradesh recognised the special attention and devotion accorded by the hon. Prime Minister and his Party to the State of Andhra Pradesh. Governments in the State, be it the present YSRCP Government or the previous TDP Government, are labelling their party stickers and making false propaganda that the houses are built under the State Schemes. In fact, no development is taking place in the State."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Member, you have started speaking in Telugu without any prior intimation. There is no interpretation facility available. Moreover, your time is going to be over. Please conclude in just one minute. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: For Andhra Pradesh, during the last seven years, we have given Rs. 35,000 crores for construction of highways. The length of highways has got doubled in just one year. It has gone double from 4,100 kilometers to 8,100 kilometers. Now, our friends in the Opposition say that this operation has been a success, but this is a failure. I would like to tell my friends that this Budget will actually revitalize India's economy. * "In 2019, Operation YCP was carried out during the elections, and YSRCP said, we will improve the conditions of the State if we are elected to power. However, today, everything in the State stands ruined and destroyed because of the operation conducted by YCP."

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am calling the next speaker, Shri Ajay Pratap Singh.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Thank you, Sir.

श्री अजय प्रताप सिंह (मध्य प्रदेश) : उपसभापति महोदय, इस बजट चर्चा पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो बजट प्रस्तुत हुआ है, मैं उस बजट के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपसभापति महोदय, बजट के संदर्भ में इस सदन में जो चर्चा चल रही है, मैं संभवत: उस चर्चा के अंतिम वक्ताओं में से हूं, इसलिए मैं न तो बजट पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा और न ही आंकड़ों की चर्चा करूंगा। मैं केवल अपने स्वार्थ की चर्चा करूंगा, अपने प्रदेश की चर्चा करूंगा। मैं इस बजट के साथ विशेष रूप से इसलिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि इस बजट में केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44 हज़ार, 6 सौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

यह परियोजना देश की पहली परियोजना है, जिसका सपना हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था कि नदियों को जोड़ने के माध्यम से भारत के वे भू-भाग जो सूखे हैं, असिंचित हैं, वहाँ पर भी हरियाली आए, वहाँ का भी किसान मजबूत हो, वहाँ पर भी फसलों का उत्पादन हो। महोदय, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र और उत्तर प्रदेश का भी बुंदेलखंड क्षेत्र, ये दोनों ही क्षेत्र सूखे की मार से प्रभावित रहते थे, लेकिन अब इस परियोजना के क्रियान्वयन के माध्मम से इन क्षेत्रों में हरियाली आएगी और 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस दिन इस क्षेत्र की 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होगी, उस दिन इस क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी, इस क्षेत्र में खुशहाली आ जाएगी, इस क्षेत्र में समृद्धि आ जाएगी। जिस बेरोज़गारी की आप चर्चा कर रहे हैं, जिस बेरोज़गारी को आप इंगित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस दिन यह 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित हो जाएगी, उस दिन किसानों को, किसानों के बेटों को, उनको अपने घर में, अपने खेत में, अपने गाँव में ही रोज़गार मिलेगा, काम मिलेगा।

3.00 P.M.

यह अभूतपूर्व योजना इस बजट में शामिल की गई, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी और आदरणीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूँ और साधुवाद भी देता हूँ।

दूसरी परियोजना है - ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन। यह बहुत पुरानी परियोजना है। इस परियोजना के बारे में जब अंग्रेजों का शासन काल था, तब visualize किया गया था। उसके बाद आजाद भारत में भी समय-समय पर इस परियोजना पर चर्चा होती रही। आजाद भारत में जब विंध्य प्रदेश बना था, तब इस परियोजना को विंध्य प्रदेश की lifeline माना गया था। विंध्य प्रदेश के तत्कालीन सभी प्रमुख नेता एकत्रित होकर केन्द्रीय नेतृत्व के पास आए थे और उन्होंने इस रेल परियोजना को स्वीकृत करने का आग्रह किया था, लेकिन उस समय का जो केन्द्रीय नेतृत्व था ...

श्री उपसभापति : माननीय अजय प्रताप जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, 3 बज चुके हैं, हम सब 15 मिनट और बैठेंगे। अभी बोलने के लिए और भी जितने speakers के नाम हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उनमें से जितना हो सके, आज बोल लें। मुझे लगता है कि 15 मिनट और बैठने की आप सबकी permission है। अजय प्रताप जी, आप बोलिये।

श्री अजय प्रताप सिंह : उस समय का जो केन्द्रीय नेतृत्व था, उसने उन विंध्य प्रदेश के नेताओं की बात पर ध्यान नहीं दिया, उनकी गुहार नहीं सुनी और यह वर्षों-वर्ष तक लंबित रही। जब कभी भी नेताओं का अधिक दबाव पड़ता था, जनता का अधिक दबाव पड़ता था, तो जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वह केवल सर्वे के नाम पर चंद लाख रुपए स्वीकृत कर देती थी और सर्वे का झुनझुना पकड़ा कर वह बात टाल दी जाती थी। अगर पहली बार यह परियोजना budgeted हुई थी, तो स्वर्गीय प्रधान मंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में budgeted हुई थी। तब यह सुनिश्चित हो गया था कि यह परियोजना बनेगी और बन कर रहेगी। उसके बीच के जो 10 साल हैं, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन यह बताना आवश्यक है कि उस 10 साल में यह परियोजना

ठंडे बस्ते में रही। जब इस देश की बागडोर हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने सँभाली, तब पहली बार उन्होंने इस परियोजना के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना शुरू किया, पहली बार इस परियोजना के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया और राष्ट्रीय पाइपलाइन में जो परियोजनाएँ सम्मिलित हैं, उस राष्ट्रीय पाइपलाइन में इस परियोजना को शामिल किया और तब से इस परियोजना पर काम तेजी से बढ़ चला है। इस वर्ष मध्य प्रदेश को रेलवे के लिए 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेलवे के इतिहास में पहली बार बजट में मध्य प्रदेश के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश हिन्दुस्तान का हृदय प्रदेश है, लेकिन रेलवे की दृष्टि से मध्य प्रदेश उतना समृद्ध प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश में रेलवे लाइन की जो दूरी है, जो किलोमीटर है, वह बहुत कम है। मध्य प्रदेश के अनेक जिले अभी भी रेल की सुविधा से वंचित हैं। अनेक मुख्यालय रेल से नहीं जुड़े हुए हैं। यह जो 12,000 करोड़ रुपए रेल के लिए दिए गए हैं, इस 12,000 करोड़ रुपए के माध्यम से न केवल ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट पूरा होगा, बल्कि हम सब यह विश्वास रखते हैं कि जब मई, 2024 में अगली लोक सभा का चुनाव आएगा, उस समय तक हमारा जिला भी रेल लाइन से जुड़ जाएगा और हमारे जिले के लोग भी रेल लाइन होने का आनंद प्राप्त कर सकेंगे। उपसभापति महोदय, ये दो विशेष प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके संदर्भ में इस बजट में मध्य प्रदेश को सौगात दी गई है। इसलिए मैं इस बजट के साथ विशेष रूप से खड़ा हूँ और इस बजट का समर्थन करता हूँ।

उपसभापति महोदय, इस बजट में आम आदमी की भी चिंता की गई है। मैं एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, एक सामान्य परिवार का प्रतिनिधित्व करता हूँ, गाँव का प्रतिनिधित्व करता हूँ, गाँव में रहने वाले समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए जब इस समाज के लिए, आम आदमी के लिए कुछ किया जाता है, तो मुझे एक संतोष होता है, एक प्रसन्नता होती है। इस बजट में आम आदमी के लिए बहुत कुछ किया गया है। हमारे विपक्षी साथियों को भले ही यह न दिखाई दे कि आम आदमी के लिए क्या किया जा रहा है, लेकिन जब हम बजट को पढ़ते हैं, तो संतोष होता है कि इस बजट में आम आदमी के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं।

आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, हम उसका अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अभी तक हम अपने गांव के लोगों को पीने का साफ भी उपलब्ध नहीं करवा पाए थे। यह कितनी बड़ी विडम्बना है। अभी तक जो शासन में रहे, वे ज़रा इस बात को सोचें कि हिन्दुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश है और इतनी पुरातन संस्कृति है, इतनी पुरातन सभ्यता है, यह सब कुछ होने के पश्चात भी अगर हम आम आदमी के जीवन का विचार करें, तो उसके पास पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं था। इस बजट में सरकार ने यह व्यवस्था की है कि गांव में रहने वाले सभी लोगों को हम साफ-सुथरा पानी, नल से जल उपलब्ध कराएंगे। केवल पानी ही नहीं, उनके लिए स्वच्छता का भी प्रावधान किया गया है और आवास का भी प्रावधान किया गया है। अभी तक 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत 2.5 करोड़ घर बन चुके हैं और इस बजट में 80 लाख और आवासों का प्रावधान किया गया है। ये जो आवास हैं, इनके बारे में आप ज़रा एक गरीब आदमी से बात करके देखिए। गरीब आदमी का सपना क्या होता है? हर गरीब आदमी का सपना यह रहता है कि मेरा जीवन तो किसी तरीके से कट गया है, लेकिन अपने बच्चों को मैं अच्छा भविष्य देकर जाऊँ, अपने बच्चों को मैं अच्छी जिन्दगी देकर जाऊँ, अपने बच्चों को मैं अच्छा घर देकर जाऊँ, अपने बच्चों को मैं अच्छा परिवेश

देकर जाऊँ। हर व्यक्ति इसके लिए प्रयास करता रहता है कि कम से कम अपने जीवन काल में मैं एक अच्छा घर तो बनाऊँ। लेकिन गांवों में रहने वाले बहुत सारे गरीब व्यक्ति सीमित साधनों के कारण, अपनी आजीविका के संकट के कारण अपने सपने को आकार नहीं दे पाते। उनके सपनों को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूरा किया है। आम आदमी से जुड़े हुए अनेक विषय हैं, जिनका उल्लेख पूर्व में हमारे कई साथियों ने भी किया है।...(**समय की घंटी**)... उदाहरण स्वरूप मैंने भी दो योजनाओं की चर्चा की थी।...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : अजय प्रताप जी, कृपया आप कन्क्लूड करिए।

श्री अजय प्रताप सिंह : यह जो बजट है, यह नये भारत का आगाज़ करता है, लेकिन कई लोगों ने इसकी खिल्ली उड़ाने का प्रयास भी किया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे मित्र श्री राकेश सिन्हा जी ने जनसंख्या सम्बन्धी एक प्राइवेट मेम्बर्स बिल प्रस्तुत किया था। लोगों को लगता था कि इस देश की इतनी बड़ी आबादी है, तो इस बड़ी आबादी की आवश्यकता और समस्या को हम किस तरीके से address करेंगे।...(**समय की घंटी**)... उसका रास्ता इस बजट के माध्यम से हमारे प्रधान मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने प्रशस्त किया है। उन्होंने जो digital university की बात की है, उससे पूरे हिन्दुस्तान का digitalization होगा। उन्होंने digital passport की बात की है।...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : अजय प्रताप जी, अब मैं दूसरे स्पीकर को बुला रहा हूं, please conclude.

श्री अजय प्रताप सिंह : उन्होंने digital currency की बात की है, उसके माध्यम से नये भारत का स्वरूप क्या होगा, यह तय किया गया है।...(**व्यवधान**)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have no time. आपकी बात अब रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। माननीय रामदास अठावले जी, आपके पास सिर्फ तीन मिनट का समय है।

श्री अजय प्रताप सिंह : *

श्री उपसभापति : माननीय रामदास अठावले जी, आपके पास सिर्फ तीन मिनट का समय है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : डिप्टी चेयरमैन सर:

---

* Not Recorded.

"2022-23 का निर्मला सीतारमण जी का बजट है 'विकास की गंगा',
कांग्रेस वालो मत लो मोदी जी से पंगा,
मत भूलो 'वरलिया रंगा', नहीं तो संकट आ जाएगा 'अंगा',
कांग्रेस ने किया है भारत को 'भकास',
लेकिन मोदी जी ने किया है भारत का विकास,
मोदी जी ने किया है अंधेरे में प्रकाश,
इसलिए दिख रहा है अब नीला-नीला आकाश।।"

डिप्टी चेयरमैन सर, यह जो बजट आया है, यह गरीबों को न्याय देने वाला, मध्यमवर्गीय लोगों को आगे जाने का मौका देने वाला, बिज़नेस करने वाले लोगों को सपोर्ट करने वाला बजट है। साथ ही यह कांग्रेस पार्टी के लोगों को, opposition के लोगों को भी प्रगति करने का मौका देने वाला बजट है। यह बजट सभी लोगों के विकास के लिए है। इस बजट में Scheduled Castes और Scheduled Tribes के जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है। 2021-22 के बजट में Scheduled Castes के लिए 1,26,259.20 करोड़ रुपये का प्रावधान था। इस साल 1,42,342.36 करोड़ रुपये का बजट शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए मिला है।

हमारे संविधान के मुख्य शिल्पी, डा. बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था - 'मेरा आदर्श एक ऐसा समाज होगा, जो स्वाधीनता, समानता और भाईचारे पर आधारित हो। प्रजातंत्र सरकार का एक स्वरूप मात्र नहीं है, प्रजातंत्र का मूल है, अपने साथियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना।' हमें इस पर कार्य करने की आवश्यकता है, तभी हम और आप हर समुदाय और हर वर्ग के लिए कल्याण कर सकेंगे और भारत को शिखर तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। बाबासाहेब अम्बेडकर जी चाहते थे कि संविधान में सामाजिक समानता के साथ-साथ आर्थिक समानता आनी चाहिए, हर वर्ग को न्याय मिलना चाहिए।

श्री उपसभापति : धन्यवाद, हाउस एड्जर्न होना है, इसके बाद लोक सभा की बैठक शुरू होगी। अब हम स्पेशल मेन्शंस लेते हैं। कृपया आप स्पीचेज़ ले करें, आप सिर्फ टाइटल पढ़ें। माननीय श्री जी.सी. चंद्रशेखर। ...*(Interruptions)*... Mr. Athawale, it is not going on record; it is not going on record. Time is over. ...*(Interruptions)*... You have already taken four minutes when your time was three minutes. ...*(Interruptions)*... Please, it is not going on record. ...*(Interruptions)*... Shri G.C. Chandrashekhar; please lay your Special Mention.

SPECIAL MENTIONS

Increasing dependence on Chinese imports

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR (Karnataka): Sir, I would like to understand the import dependency of India. Between 2019-20 and 2020-21, trade with China accounted for 12.62 per cent of India's total trade with the world. Imports to India from China reached nearly 100 billion dollars for the first time.

India's top ten imports from China mostly comprised machinery and mechanical appliances and these top ten imports accounted for nearly 20 per cent of India's total imports. As per recent data, even in the import of medical equipment, China was the first among the top three countries; it was among the top three earlier.

We have increased trade with China by six per cent. It is 86.4 billion dollars higher than India's trade with the other countries. India's exports rose from 5.08 per cent in 2018-19 to 7.28 per cent in 2020-21. On the imports side, the share of China rose from 13.68 per cent to 16.57 per cent during the same period, while India's trade with the world declined by 13 per cent.

Import of medical devices stood at 6,240 million dollars, which is three times bigger than exports. In this, China contributes 1,110.0 million US dollars, which is 17.8 per cent.

I would urge the Ministry to clarify the status of self-reliance, keeping in mind the aspirations, sensitivities and interests of the common citizens.

Need to expedite the process of transfer of Railway land to Dharavi Redevelopment Project in Mumbai

SHRIMATI PRIYANKA CHATURVEDI (Maharashtra): Sir, an MOU was executed between the Railway Land Development Authority (RLDA) and Dharavi Redevelopment Project (DRP) on 03.03.2019 to hand over 45 acres of land for Dharavi Redevelopment Project.

The Government of Maharashtra made full payment of Rs.800 crore to the Railway Land Development Authority in June, 2019. However, the 45 acres of railway land has not yet been transferred to Dharavi Redevelopment Project. Further, draft definitive agreement forwarded by RLDA differs from the terms and condition agreed in the MOU. The Maharashtra Government has been actively following up on these issues, but no definitive progress has been made. The concerned matters were also discussed in the meeting of the NITI Aayog held on 14.09.2021.